bjpkamaljyoti@gmail.com www.up.bjp.org संवत 2080 युगाब्द 5125 कुल पृष्ठ –32 जुलाई प्रथम अंक – 23

वर्तमान कमल ज्योति

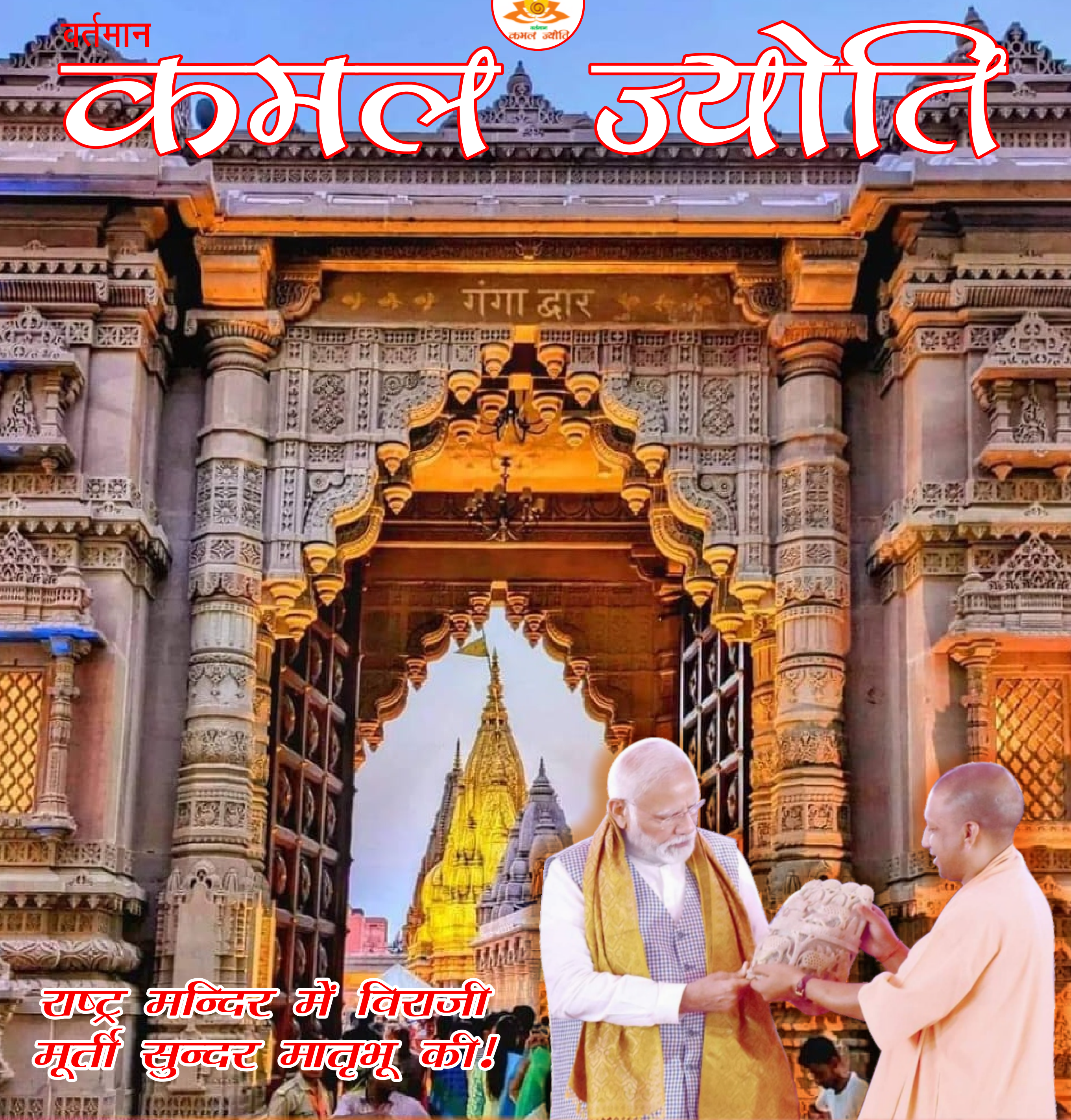

राष्ट्र मन्दिर में विराजी मूर्ती सुन्दर मातृभू की!

₹20

वर्तमान

कमल ज्योति

संरक्षक
श्री भूपेन्द्र सिंह
सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी
प्रबन्ध/कार्यकारी सम्पादक
राजकुमार
प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह
पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

www.up.bjp.org
bjpkamaljyoti
bjpkamaljyoti
@bjpkamaljyoti

पवित्र श्रावणमास की हार्दिक शुभकामनायें

सम्पादकीय

भद्रलोक के लोकतंत्र पर्व में हिंसा?

वर्तमान लोकतांत्रिक राजनीति में पश्चिम बंगाल में सम्पन्न हुए पंचायत चुनाव के परिणाम चाहे जो रहे हो। लेकिन मानवीयता के नाम पर ऐसी चुनावी हिंसा कलंक है। सत्ताधारी दल द्वारा विपक्ष पर आरोप मढ़ना और दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लोकतंत्र का भीड़तंत्र–लाठीतंत्र में बदलना कहाँ तक उचित है? दूसरी तरफ देश के तथाकथित राजनैतिक दलों की चुप्पी चिन्ता का विशय है।

पश्चिम बंगाल में टीएमसी पंचायत चुनाव में जीत का जश्न मना रही है। भारतीय जनता पार्टी परिणामों में दूसरे स्थान पर है। इस जश्न में उन परिवारों की चीत्कार कहीं खो गई, जिनके परिजन चुनावी हिंसा के शिकार हुए। खून से सने पोलिंग बूथ, टूटी मतपेटियां और बुलेट–बम की खौफनाक तस्वीरें भी जश्न के सुनहरे रंग में खो जाएंगी। यह जीत इसकी गारंटी नहीं है कि अगले चुनावों में यहां हिंसा नहीं होगी। आखिर चुनावों के दौरान बंगाल में हिंसा क्यों होती है? क्या यह पश्चिम बंगाल की नीयती है या सरकारी तंत्र की विफलता। चुनाव आयोग या सरकार, किसी न किसी को इन मौतों की जिम्मेदारी लेनी होगी। ममता दीदी की तृणमूल सरकार आखिर किस प्रकार की लोकतंत्र चाहती है? लाठी तंत्र से लोकतंत्र कैसे सुरक्षित होगा?

बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान 16 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद भी 9 हत्याएं हुई थीं। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद भी 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। 2018 के पंचायत चुनाव में भी बंगाल में 23 लोग मारे गए थे। इससे पहले भी चुनावों में राजनीतिक हत्याएं होती रही हैं। नक्सलबाड़ी के लिए मशहूर बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का इतिहास ज्यादा पुराना है। 1971 में कांग्रेस के सिद्धार्थ शंकर रे के शासनकाल में शुरू हुआ हिंसा का दौर आज तक नहीं थमा। कांग्रेस के बाद सीपीएम, फिर टीएमसी सत्ता में आई। लंबे समय तक ज्योति बसु, बुद्धदेब भट्टाचार्य और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी पर काबिज रहीं मगर इनके राज में हिंसा नहीं रुका। 2011 में वाम दलों का किला ढहा तब यह उम्मीद जताई गई कि ममता बनर्जी इस रक्तरंजित गाथा पर पूर्णविराम लगाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी के शासनकाल में भी 12 साल से बंगाल चुनावों में लहूलुहान हो ही रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े बताता हैं कि 10 साल के शुरुआती ममता राज में 150 लोग चुनावी हिंसा के शिकार हुए। अब तो चुनावी हिंसा भद्रलोक के बंगाल की संस्कृति बन गई है। सोनार बांग्ला की संकल्पना में जीने वाला देश अपने इस प्रदेश को चुनावी हिंसा से कब मुक्ति पायेगा?

राजनीतिक हिंसा का दौर वर्चस्व की लड़ाई में सीपीएम के कैडर्स ने वोटरों को धमकाना शुरू किया। अपने–अपने इलाकों में पार्टी के लिए ज्यादा वोट जुटाने वाले कैडर पार्टी में बड़े ओहदों पर बैठाए गए। थाना और प्रशासन में उनका दखल बढ़ा। जिन कार्यकर्ताओं का कद बढ़ा, वह खनन माफिया बन गए। उनका नियंत्रण बालू और कोयला खदानों, कट मनी पर होने लगा। इन कार्यकर्ताओं के बढ़ते कद ने बंगाल को राजनीतिक हिंसा के लिए प्रेरित किया। 2011 तक पहले कांग्रेस, फिर टीएमसी माकपा से यह लड़ाई रहती रही। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता पर कब्जा किया तो राजनीतिक तौर से बंगाल में परिवर्तन हुआ, मगर ग्राउंड पर दबंगई और माइनिंग माफिया वाला नेटवर्क बना रहा। वामपंथी दलों के दबंग नेता और माफिया पांच साल में तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा बन चुके थे। राजनीति की मजबूरी है कि ऐसे लोगों को सत्ता दंडित नहीं कर सकती है। इधर के दिनों में भाजपा तेजी से बंगाल में बढ़ रही है तो तृणमूल माकपा, काँग्रेस सबकी आँखों की किरकिरी बनी हुई है। सब मिल हिंसा के सहारे इसे रोकने के प्रयास कर रहे हैं। जो हिंसा के सहारे लोकतंत्र को खतरे के संकेत है। पश्चिम बंगाल चुनाव में पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग हिंसा की चपेट में आये हैं। निरिह परिवारों को हिंसा की आग में झुलसने के बाद आखिर इन परिवारों का सहारा कौन बनेगा? सद्भावना शांति गाँवों में कैसे बहाल होगी। इसका सभी राजनैतिक दलों को प्रयास, करना होगा।

bjpkamaljyoti@gmail.com

अब जे भी बनारस आई, त खुश हो के जाई!

प्रधानमंत्री मोदी जी की अपनी काशी, प्यारी काशी, न्यारी काशी जिसके प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। उनका संकल्प है कि काशी क्वेटो जैसे बनेगी। उनका निरन्तर प्रयास सांस्कृतिक राजधानी को गरिमा के अनुरूप निखरती जा रही है। उनके हृदय के काशी वासियों के लिए स्नेह है उन्हें जब भी समय मिलता है। बनारस के रस में सराबोर हो जाते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि सावन के महीने की शुरुआत हो बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद हो और बनारस के लोगों का साथ हो, फिर तो जीवन बिल्कुल धन्य हो जाता है। मैं जानता हूं कि आजकल काशी के आप लोग बहुत व्यस्त हैं, काशी में रौनक जरा ज्यादा ही हो रही है आजकल। देश–दुनिया से हजारों शिवभक्त यहां हर रोज बाबा को जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं और इस बार तो सावन की अवधि भी जरा अधिक है। ऐसे में इस बार बाबा के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं का आना तय है। लेकिन इन सबके साथ एक और बात तय है। अब जे भी बनारस आई, त खुश होके ही जाई! मुझे बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती कि इतने सारे लोग आएंगे, बनारस में सब कैसे मैनेज होगा। काशी के लोग तो मुझे सिखा देते हैं, मैं उनको कोई चीज नहीं सिखा सकता हूं। अभी जी–20 के लिए दुनिया भर से इतने सारे लोग बनारस आए थे। काशी के लोगों ने उनका इतना भव्य स्वागत किया, इतना अच्छा प्रबंध किया कि आज पूरे दुनिया में आपकी और काशी की वाहवाही हो रही है। और इसलिए मुझे पता है काशी के लोग सब संभाल लेंगे। आप लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम और पूरे परिसर को भी इतना भव्य बनवा दिया है कि जो यहां आ रहा है, गदगद होकर जा रहा है। ये बाबा की इच्छा ही थी कि हम उसे पूरा करने का निमित बन पाए। ये हम सभी का सौभाग्य है।

आज काशी सहित उत्तर प्रदेश को लगभग 12 हज़ार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार मिला है। हमने जो काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए नूतन काया का संकल्प लिया है, ये उसका विस्तार है। इनमें रेल, रोड, पानी, शिक्षा, टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, घाटों के पुनर्विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत–बहुत बधाई।

कुछ देर पहले ही मेरी प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से बातचीत हुई। पहले की सरकारों से लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो योजनाएं एयरकंडीशन्ड कमरों में बैठकर बनाती थी। जमीन पर उन योजनाओं का क्या असर हो रहा है, ये तब की सरकारों को पता ही नहीं चलता था। लेकिन भाजपा सरकार ने लाभार्थियों से बात की, संवाद की, मुलाकात की, एक नई परंपरा शुरू की है। यानि बेनिफिट भी डायरेक्ट और फीडबैक भी डायरेक्ट। इसका

फायदा ये हुआ कि हर सरकारी विभाग, हर अफसर अपनी जिम्मेदारी समझने लगे। अब किसी के लिए गुणा–गणित का कोई चांस ही नहीं बचा है।

जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाईं, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद, लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है। वरना पहले लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ गिने–चुने लोगों के हित साधे जाते थे, गरीब की कोई पूछ ही नहीं थी। भाजपा सरकार में लाभार्थी वर्ग आज सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेकुलरिज्म का उदाहरण बन गया है। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हर योजना के आखिरी लाभार्थी को खोजकर, उस तक पहुंचकर, उसे योजना का लाभ पहुंचाएं। जानते हैं इसका सबसे बड़ा लाभ क्या हो रहा है? भाई जब, सरकार खुद ही पहुंच रही है तो क्या हो रहा है? कमीशन लेने वालों की दुकान३.बंद। दलाली खाने वालों की दुकान३बंद। घोटाले करने वालों की दुकान३बंद। यानी ना कोई भेदभाव और ना ही कोई भ्रष्टाचार।

बीते 9 वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए, इसको ध्यान में रखकर के काम किया है। अब जैसे गरीबों के घर की योजना है। अभी तक देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिल चुके हैं। आज भी यहां यूपी के साढ़े चार लाख गरीब परिवारों को पक्के घर सुपुर्द किए गए हैं। सावन के महीने में महादेव की ये कितनी बड़ी कृपा हुई है।

जिन गरीबों को ये घर मिले हैं, उनकी एक बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाती है, सुरक्षा की भावना उनके भीतर आ जाती है। जिन्हें ये घर मिलता है, उनमें एक नया स्वाभिमान जागता है, नई ऊर्जा आती है। जब ऐसे घर में कोई बच्चा पलता है, बढ़ता है, तो उसकी आकांक्षाएं भी अलग होती हैं। और आपको एक बात मैं बार–बार याद दिलाता हूं। पीएम आवास योजना के ये ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर मिल रहे हैं। आज इन घरों की कीमत कई–कई लाख रुपए हो गई है। करोड़ों बहनें तो ऐसी हैं, जिनके नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। इससे गरीब परिवारों की बहनों को जो आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली है, ये वो ही जानती हैं।

आयुष्मान भारत योजना भी सिर्फ 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक पड़ा रहता है। जब गरीब परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो किसी की पढ़ाई छूट जाती है, किसी को छोटी उम्र में काम करने के लिए जाना पड़ता है। पत्नी का भी रोजी रोटी के लिए निकलना पड़ता है। एक गंभीर बीमारी आई कि कई–कई साल तक मां–बाप बच्चे बड़े हो जाए लेकिन शादी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आर्थिक स्थिति बीमारी में खस्ता हाल हो जाती है। और गरीब के सामने दो ही विकल्प होते हैं। या तो वो अपनों को अपनी आंखों के सामने ज़िंदगी के लिए संघर्ष करते देखे, या घर–खेत बेच दे, किसी से इलाज के लिए कर्ज़ ले। जब प्रॉपर्टी बिकती है, कर्ज़ का बोझ बढ़ता है, तो आने वाली कई–कई पीढ़ियां प्रभावित हो जाती हैं। आयुष्मान भारत योजना आज गरीब को इसी संकट से बचा रही है। इसलिए मैं मिशन मोड पर लाभार्थियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने के लिए इतना अधिक प्रयास कर रहा हूं। आज भी यहां से एक करोड़ 60 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड बंटना शुरू हुआ है।

देश के संसाधनों पर वंचितों का, गरीबों का सबसे बड़ा हक होता है। पहले बैंक तक पहुंच भी सिर्फ अमीर लोगों की होती थी। गरीबों के लिए तो ये माना जाता था कि पैसा ही नहीं है, तो बैंक खाते का क्या करेंगे? कुछ लोग सोचते थे कि गारंटी देने के लिए कोई नहीं है, तो बैंक लोन कैसे मिल पाएगा। बीते 9 वर्षों में इस सोच को भी भाजपा सरकार ने बदल दिया। हमने बैंकों के दरवाज़े सबके लिए खोल दिए। हमने करीब–करीब 50 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले। मुद्रा योजना के तहत 50 हज़ार से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण बिना गारंटी दिए। यहां यूपी में भी करोड़ों लाभार्थियों ने मुद्रा योजना का लाभ उठाकर अपना काम शुरू किया है। इसमें सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक परिवारों से जुड़े साथियों और महिला उद्यमियों को हुआ है। यही तो सामाजिक न्याय है, जिसकी गारंटी भाजपा सरकार दे रही है।

हमारे रेहड़ी–ठेले–पटरी–फुटपाथ पर छोटा–मोटा व्यवसाय करने वाले साथी भी अधिकतर वंचित समाज से ही आते हैं। लेकिन पहले की सरकारों ने इन साथियों को भी सिवाय अपमान और प्रताड़ना के कुछ नहीं दिया। रेहड़ी–ठेले–पटरी–फुटपाथ पर दुकान चलाने वालों को दुत्कार देता है, गाली देकर चला जाता है। लेकिन गरीब मां का बेटा मोदी, इनका ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने रेहड़ी–ठेले–पटरी–फुटपाथ पर

दुकान चलाने वालों के लिए पीएम–स्वनिधि योजना बनाई है। हमने पीएम स्वनिधि योजना के तहत इनको भी सम्मान दिया है और बैंकों को इन्हें मदद देने को कहा है। जो पैसे पटरी वाले दुकानदारों को बैंक दे रहे हैं, उसकी गारंटी भी सरकार खुद ले रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अभी तक 35 लाख से अधिक साथियों को मदद स्वीकृत की गई है। यहां बनारस में भी आज सवा लाख से ज्यादा लाभार्थियों को स्वनिधि योजना के तहत लोन दिए गए हैं। इस लोन से वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे, अपनी दुकान का विस्तार करेंगे। अब कोई उन्हें गाली नहीं दे पाएगा, उन्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा। गरीब को स्वाभिमान, ये है मोदी की गारंटी है।

जिस लोगों ने देश पर दशकों तक राज किया, उनके शासन के मूल में ही बेईमानी रही। और जब ऐसा होता है तो चाहे कितना भी धन इकट्ठा हो, तो कम ही पड़ता है। 2014 से पहले भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों की सरकारों के दौरान ऐसा ही कारोबार चलता था। बजट की जब भी बात आती थी, तो घाटे का, नुकसान का ही बहाना होता था। आज गरीब कल्याण हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट की कोई कमी नहीं है। वही करदाता हैं, वही सिस्टम है। लेकिन सरकार बदली है, नीयत बदली है, तो परिणाम भी बदले दिख रहे हैं। पहले करप्शन और कालाबाज़ारी की खबरों से अखबार भरे रहते थे। अब नए प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास और लोकार्पण की खबरें अखबारों में छाई रहती हैं। बीते 9 वर्षों में आए परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण, भारतीय रेल है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानि मालगाड़ियों के लिए विशेष पटरियों की योजना 2006 में शुरु हुई थी। लेकिन 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बिछ पाया था। एक किलोमीटर भी नहीं। पिछले 9 वर्षों में इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। इस पर मालगाड़ियां चलनी शुरु कर चुकी हैं। आज भी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू सोननगर खंड का लोकार्पण किया गया है। इससे मालगाड़ियों की स्पीड तो बढ़ेगी ही, पूर्वांचल में, पूर्वी भारत में रोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे।

जब नीयत साफ होती है तो कैसे काम होता है, इसका एक और उदाहरण मैं देता हूं। देश में तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलें, देश हमेशा ये चाहता था। इसके लिए पहली बार देश में करीब–करीब 50 साल पहले राजधानी एक्सप्रेस की शुरूआत हुई। राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई। लेकिन इतने साल में भी ये राजधानी एक्सप्रेस सिर्फ 16 रूटों में ही चल पाई है। पचास सालों में सिर्फ सोलर रूट इसी तरह 30–35 साल पहले शताब्दी एक्सप्रेस भी चली पड़ी। लेकिन शताब्दी ट्रेन भी 30–35 साल में अब तक 19 रूटों पर ही सेवा दे रही है। इन ट्रेनों से अलग, एक वंदेभारत एक्सप्रेस है। और बनारस के पास तो देश की पहली वंदेभारत का खिताब है। 4 साल में ये ट्रेन 25 रूट्स पर चलनी शुरू हो चुकी है। आज भी गोरखपुर से दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। एक ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ के लिए चली है और दूसरी अहमदाबाद से जोधपुर रूट पर चली है। देश के मध्यम वर्ग में ये वंदे भारत इतनी सुपरहिट हो गई है, कि कोने–कोने से इसके लिए डिमांड आ रही है। वो दिन दूर नहीं, जब वंदेभारत, देश के कोने–कोने को कनेक्ट करेगी।

बीते 9 वर्षों में काशी की कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। यहां जो विकास कार्य हो रहे हैं, वो रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बना रहे हैं। अब जैसे पिछले वर्ष काशी में 7 करोड़ से ज्यादा पर्यटक और श्रद्धालु आए थे। सिर्फ एक साल में काशी आने वाले पर्यटकों की संख्या में 12 गुना बढ़ोतरी हुई। 12 गुना पर्यटक बढ़े हैं, तो इसका सीधा लाभ यहां के रिक्शा वाले को हुआ है, दुकानदारों को हुआ है, ढाबा–होटल चलाने वाले साथियों को हुआ है। बनारसी साड़ी का काम करने वाले हों, या फिर बनारसी पान वाले मेरे भाई, सभी को इससे बहुत फायदा हो रहा है। पर्यटक बढ़ने का बहुत बड़ा लाभ हमारे नाव वाले साथियों को हुआ है। शाम को जो गंगा आरती होती है, उस समय नावों पर कितनी भीड़ होती है, ये देख मैं भी हैरत में पड़ जाता हूं। आप लोग ऐसे ही बनारस को संभाले रहिए। बाबा के आशीर्वाद से वाराणसी के तेज़ विकास की ये यात्रा चलती रहेगी। और मैं इस बार काशीवासियों का और भी धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछले दिनों काशी में नगर निगम के चुनाव हुए थे। आप सबने विकास की यात्रा समर्थन किया, विकास में विश्वास करने वालों को जीताकर के भेज दिया और काशी में एक अच्छा व्यवस्था खड़ी करने की दिशा में आप लोगों ने जो सहयोग दिया तो काशी के सांसद के नाते आप सब के इस सहयोग के लिए मैं जब आपके बीच आया हूं तो ह्रदय से आपाका आभार भी व्यक्त करता हूं।

गोरखनाथ की तपस्थली में विकास भी विरासत भी

कार्यक्रम में गीता प्रेस शताब्दी समारोह पर नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि सावन का पवित्र मास, इंद्रदेव का आशीर्वाद, शिवावतार गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली, और अनेकानेक संतों की कर्मस्थली ये गीताप्रेस गोरखपुर! जब संतों का आशीर्वाद फलीभूत होता है, तब इस तरह के सुखद अवसर का लाभ मिलता है। मेरा गोरखपुर का दौरा, 'विकास भी, विरासत भी' इस नीति का एक अद्‌भुत उदाहरण है। मुझे अभी चित्रमय शिव पुराण और नेपाली भाषा में शिव पुराण के विमोचन का सौभाग्य मिला है। गीता प्रेस के इस कार्यक्रम के बाद मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाऊंगा। आज से ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम भी शुरू होने जा रहा है। और मैंने जब से सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें डाली हैं, लोग हैरान होकर के देख रहे हैं। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि रेलवे स्टेशनों का भी इस तरह कायाकल्प हो सकता है। और उसी कार्यक्रम में, मैं गोरखपुर से लखनऊ के लिए वन्दे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाऊंगा। और उसी समय जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन ने, देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी है।

गीताप्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है, जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि, एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय, करोड़ों–करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है, और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता हैदृ वहाँ साक्षात् कृष्ण हैं। और जहां कृष्ण हैं। वहाँ करुणा भी है, कर्म भी हैं। वहाँ ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है। क्योंकि, गीता का वाक्य है– **'वासुदेवः सर्वम्'**। सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ वासुदेव से ही है, सब कुछ वासुदेव में ही है।

1923 में गीताप्रेस के रूप में यहाँ जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्ज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस मानवीय मिशन की शताब्दी के साक्षी बन रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर ही हमारी सरकार ने गीताप्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया है। गांधी जी का गीता प्रेस से भावनात्मक जुड़ाव था। एक समय में, गांधी जी, कल्याण पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे। और मुझे बताया गया कि गांधी जी ने ही सुझाव दिया था कि कल्याण पत्रिका में विज्ञापन न छापे जाएँ। कल्याण पत्रिका आज भी गांधी जी के उस सुझाव का शतदृप्रतिशत अनुसरण कर रही है। मुझे खुशी है कि आज ये पुरस्कार गीताप्रेस को मिला है। ये देश की ओर से गीताप्रेस का सम्मान है, इसके योगदान का सम्मान है, और इसकी 100 वर्षों की विरासत का सम्मान है। इन 100 वर्षों में गीताप्रेस द्वारा करोड़ों–करोड़ो किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। आंकड़ा कभी कोई 70 बताता है, कोई 80 बताता है, कोई 90 करोड़ बताता है ! ये संख्या किसी को भी हैरान कर सकती है। और ये पुस्तकें लागत से भी कम

मूल्य पर बिकती हैं, घर–घर पहुंचाई जाती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, इस विद्या प्रवाह ने कितने ही लोगों को आध्यात्मिक–बौद्धिक तृप्ति दी होगी। समाज के लिए कितने ही समर्पित नागरिकों का निर्माण किया होगा। मैं उन विभूतियों का अभिनंदन करता हूँ, जो इस यज्ञ में निष्काम भाव से, बिना किसी प्रचार के, अपना सहयोग देते रहे हैं। मैं इस अवसर पर सेठ जी श्री जयदयाल गोयंदका, और भाईजी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसी विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ।

गीताप्रेस जैसी संस्था सिर्फ धर्म और कर्म से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि इसका एक राष्ट्रीय चरित्र भी है। गीताप्रेस, भारत को जोड़ती है, भारत की एकजुटता को सशक्त करती है। देशभर में इसकी 20 शाखाएँ हैं। देश के हर कोने में रेलवे स्टेशनों पर हमें गीताप्रेस का स्टॉल देखने को मिलता है। 15 अलग–अलग भाषाओं में यहाँ से करीब 16 सौ प्रकाशन होते हैं। गीताप्रेस अलग–अलग भाषाओं में भारत के मूल चिंतन को जनदृजन तक पहुंचाती है। गीताप्रेस एक तरह से 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को प्रतिनिधित्व देती है।

गीताप्रेस ने अपने सौ वर्षों की ये यात्रा एक ऐसे समय में पूरी की है, जब देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। इस तरह के योग केवल संयोग नहीं होते। 1947 के पहले भारत ने निरंतर अपने पुनर्जागरण के लिए अलग–अलग क्षेत्रों में प्रयास किए। अलग–अलग संस्थाओं ने भारत की आत्मा को जगाने के लिए आकार लिया। इसी का परिणाम था कि 1947 आते–आते भारत मन और मानस से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। गीताप्रेस की स्थापना भी इसका एक बहुत बड़ा आधार बनी। सौ साल पहले का ऐसा समय जब सदियों की गुलामी ने भारत की चेतना को धूमिल कर दिया था। आप भी जानते हैं कि इससे भी सैकड़ों साल पहले विदेशी आक्रांताओं ने, हमारे पुस्तकालयों को जलाया था। अंग्रेजों के दौर में गुरुकुल और गुरु परंपरा लगभग नष्ट कर दिये गए थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि, ज्ञान और विरासत लुप्त होने की कगार पर थे। हमारे पूज्य ग्रंथ गायब होने लगे थे। जो प्रिंटिंग प्रेस भारत में थे वो महंगी कीमत के कारण सामान्य मानवी की पहुँच से दूर थे। आप कल्पना करिए, गीता और रामायण के बिना हमारा समाज कैसे चल रहा होगा? जब मूल्यों और आदर्शों के स्रोत ही सूखने लगें, तो समाज का प्रवाह अपने आप थमने लगता है।

दो वन्दे भारत ट्रेनें रवाना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन से दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। दो वंदे भारत ट्रेन हैं – गोरखपुर–लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर–अहमदाबाद (साबरमती) वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री ने लगभग 498 करोड़ की लागत से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास भी किया और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित मॉडल का निरीक्षण किया।

प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर से सांसद श्री रवि किशन भी मौजूद थे।

गोरखपुर–लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से होकर गुजरेगी और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ राज्य के महत्वपूर्ण शहरों के रेल–परिवहन संपर्क में सुधार करेगी। जोधपुर–साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस, क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए जोधपुर, आबू रोड और अहमदाबाद जैसे प्रसिद्ध स्थानों के लिए रेल–परिवहन संपर्क का विस्तार करेगी।

लगभग 498 करोड़ रुपये की लागत से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास भी किया गया है। पुनर्विकसित होने के बाद, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्राप्त होंगी।

लेकिन साथियों, हमें एक बात और याद रखनी है। हमारे भारत की अनादि यात्रा में ऐसे कितने ही पड़ाव आए हैं, जब हम और, और ज्यादा परिष्कृत होकर के निकले हैं। कितनी ही बार अधर्म और आतंक बलवान हुआ है, कितनी ही बार सत्य पर संकट के बादल मंडराएं हैं, लेकिन तब हमें श्रीमद् भागवत गीता से ही सबसे बड़ा विश्वास मिलता है–

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत्।
अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्॥

अर्थात्, जब–जब धर्म की सत्ता पर, सत्य की सत्ता पर संकट आता है, तब तब ईश्वर उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। और, गीता का दसवां अध्याय बताता है कि ईश्वर कितनी ही विभूतियों के रूप में सामने आ सकते हैं। कभी कोई संत आकर समाज को नई दिशा दिखाते हैं। तो कभी गीताप्रेस जैसी संस्थाएं मानवीय मूल्यों और आदर्शों को पुनर्जीवित करने के लिए जन्म लेती हैं। इसीलिए ही, 1923 में जब गीताप्रेस ने काम करना शुरू किया तो भारत के लिए भी उसकी चेतना और चिंतन का प्रवाह तेज हो गया। गीता समेत हमारे धर्मग्रंथ फिर से घर–घर गूंजने लगे। मानस फिर से भारत के मानस से हिल–मिल गई। इन ग्रन्थों से पारिवारिक परम्पराएँ और नई पीढ़ियां जुड़ने लगीं, हमारे पवित्र ग्रंथ आने वाली पीढ़ियों की थाती बनने लगे।

गीताप्रेस इस बात का भी प्रमाण है कि जब आपके उद्देश्य पवित्र होते हैं, आपके मूल्य पवित्र होते हैं तो सफलता आपका पर्याय बन जाती है। गीताप्रेस एक ऐसा संस्थान है, जिसने हमेशा सामाजिक मूल्यों को समृद्ध किया है, लोगों को कर्तव्य पथ का रास्ता दिखाया है। गंगा जी की स्वच्छता की बात हो, योग विज्ञान की बात हो, पतंजलि योग सूत्र का प्रकाशन हो, आयुर्वेद से जुड़ा आरोग्य अंक' हो, भारतीय जीवनशैली से लोगों को परिचित करवाने के लिए **'जीवनचर्या अंक'** हो, समाज में सेवा के आदर्शों को मजबूत करने के लिए **'सेवा अंक'** और **'दान महिमा'** हो, इन सब प्रयासों के पीछे, राष्ट्रसेवा की प्रेरणा जुड़ी रही है, राष्ट्र निर्माण का संकल्प रहा है।

संतों की तपस्या कभी निष्फल नहीं होती, उनके संकल्प कभी शून्य नहीं होते। इन्हीं संकल्पों का परिणाम है कि, आज हमारा भारत सफलता के नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। मैंने लालकिले से कहा था, और आपको याद होगा, मैंने लालकिले से कहा था कि ये समय गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का समय है और इसीलिए, शुरुआत में भी मैंने कहा, आज देश विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आज एक ओर भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी में नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो साथ ही, सदियों बाद काशी में विश्वनाथ धाम का दिव्य स्वरूप भी देश के सामने प्रकट हुआ है। आज हम वर्ल्डक्लास इनफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो साथ ही केदारनाथ और महाकाल महालोक जैसे तीर्थों की भव्यता के साक्षी भी बन रहे हैं। सदियों बाद अयोध्या में भव्य राममंदिर का हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। हम आज़ादी के 75 साल बाद भी अपनी नौसेना के झंडे पर गुलामी के प्रतीक चिन्ह को ढो रहे थे। हम राजधानी दिल्ली में, भारतीय संसद के बगल में अंग्रेजी परम्पराओं पर चल रहे थे। हमने पूरे आत्मविश्वास के साथ इन्हें बदलने का काम किया है। हमने अपनी धरोहरों को, भारतीय विचारों को वो स्थान दिया है, जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसीलिए, अब भारत की नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का निशान दिखाई दे रहा है। अब गुलामी के दौर का राजपथ, कर्तव्यपथ बनकर कर्तव्य भाव की प्रेरणा दे रहा है। आज देश की जन–जातीय परंपरा का सम्मान करने के लिए, देश भर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूज़ियम बनाए जा रहे हैं। हमारी जो पवित्र प्राचीन मूर्तियाँ चोरी करके देश के बाहर भेज दी गईं थीं, वो भी अब वापस हमारे मंदिरों में आ रही हैं। जिस विकसित और आध्यात्मिक भारत का विचार हमारे मनीषियों ने हमें दिया है, आज हम उसे सार्थक होता हुआ देख रहे हैं। मुझे विश्वास है, हमारे संतों–ऋषियों, मुनियों उनकी आध्यात्मिक साधना भारत के सर्वांगीण विकास को ऐसे ही ऊर्जा देती रहेगी। हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे, और विश्व कल्याण की अपनी भावना को सफल बनाएँगे। इसी के साथ आप सभी ने इस पवित्र अवसर पर मुझे आपके बीच आने का मौका दिया और मुझे भी इस पवित्र कार्य में कुछ पल के लिए क्यों नहीं आपके बीच बिताने का अवसर मिला, मेरे जीवन का ये सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, गीताप्रेस के श्री केशोराम अग्रवाल जी, श्री विष्णु प्रसाद जी, सांसद रवि किशन जी, अन्य महानुभाव, की उपस्थिती थी।

हर घर की दहलीज तक सम्पर्क...

केन्द्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर संगठन द्वारा पूरे देश भर सम्पर्क महाअभियान तेज हैं। अनेक चुनौतियों का सामना करते कार्यकर्ता घर–घर पहुंचने का प्रयास कर रहा हे। उत्तर प्रदेश में भी अभियान सफल रहा है। लेकिन अनेक घर अभी भी छूटे हुए हैं। इनको पूर्णता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त विशेष प्रयास हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि महा–जनसम्पर्क अभियान के तहत विगत सभी कार्यक्रम व अभियान सफल व प्रभावी रहे है। सम्पर्क से समर्थन तथा घर–घर सम्पर्क अभियान के लिए एक बार फिर जुटना है और हर घर की दहलीज तक पहुंचना है। प्रभावी अभियान के लिए शक्ति केन्द्र पर जिम्मेदारियां तथा जवाबदेही तय की जाए और कार्ययोजना बनाकर सघन जनसम्पर्क के द्वारा केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाया जाए। जिलापंचायत अध्यक्ष तथा सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, सहकारिता क्षेत्र से जुड़े पार्टी के नेताओं के साथ पार्टी पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता मिलकर प्रत्येक गांव में मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाये। विपक्ष के झूठ, फरेब व षडयंत्रकारी राजनीति का जवाब मोदी सरकार व योगी सरकार की गरीब कल्याणकारी नीतियां, सुशासन, सशक्त कानून व्यवस्था, राष्ट्रहित में समर्पित भाजपा सरकारों का प्रत्येक निर्णय तथा देश व प्रदेश का चहुंमुखी विकास है।

प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि महा–जनसम्पर्क अभियान के तहत 15 जुलाई तक प्रत्येक घर तक जनसम्पर्क सुनिश्चित करना है। सम्पर्क से समर्थन अभियान के तहत प्रत्येक लोकसभा में एक हजार विशिष्ठ जनों से सम्पर्क करना है। घर–घर सम्पर्क अभियान के माध्यम से प्रत्येक घर तक केन्द्र सरकार की उपलब्धियों का पत्रक लेकर जनमानस से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद तथा जनसमर्थन प्राप्त करना है। अभियान के तहत जिला प्रभारी जिलों में प्रवास करेंगे। वहीं मण्डल प्रभारी शक्तिकेन्द्रों पर प्रवास सुनिश्चित कर बूथ अध्यक्षों के साथ अभियान को गति देंगे। विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय परिसरों में शिक्षकों तथा युवाओं के बीच सम्पर्क से समर्थन अभियान के माध्यम से 9090902024 पर मिस्ड कॉल के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के लिए समर्थन।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी भाजपा जिला कार्यालय अम्बेडकरनगर में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ महा–जनसम्पर्क अभियान की समीक्षा तथा आगामी अभियानों व कार्यक्रमों पर चर्चा कर रहे थे। श्री चौधरी ने सम्पर्क से समर्थन अभियान के तहत जिले के वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री राम प्रसाद प्रजापति से सम्पर्क कर भाजपा सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धि से संबंधित पत्रक भेंट किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं तथा राजनैतिक

दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लिए गए निर्णयों ने जरूरतमंदो को आवास, बिजली, पानी, राशन, गैस कनेक्शन, शौचालय, शिक्षा व चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था की है। वहीं सड़क, सुरक्षा, मजबूत एमएसएमई सेक्टर, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा ऋण, जनधन खातों से निर्बल आय वर्ग को सबल करने का काम किया है। किसान सम्मान निधि, एमएसपी में बढोत्तरी, फसल बीमा योजना से किसानों की समृद्धि का संकल्प लेकर सरकार काम कर रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण के 9 वर्ष देश को नई दिशा देने वाले साबित हुए हैं। गरीब को घर, बिजली, पानी, पढ़ाई व दवाई की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई और देश आर्थिक व सामरिक रूप से शक्ति सम्पन्न भी हुआ है। भारत के बढ़ते हुए महत्व को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। धारा 370 की समाप्ति, तीन तलाक पर रोक, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, कुशल कोविड प्रबंधन, भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा पर विश्वास से कोविड वैक्सिन का निर्माण जैसे निर्णयों ने भारत की राजनैतिक दृढ़ इच्छा शक्ति को विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। मोदी जी के नेतृत्व में जनधन खातों से हुई शुरूआत और डिजिटल इंडिया मिशन से आगे बढ़ते हुए देश ने गरीबों तथा आम नागरिकों का हक मारने वाली बिचौलिया तथा कमीशनखोर कल्चर को समाप्त किया है।

देश संतुष्टिकरण अर्थात सबके विकास की नीति पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा सरकार ने सुशासन तथा सख्त कानून व्यवस्था से भय के वातावरण को समाप्त कर प्रदेश में मां, बहन, बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित की है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश की प्रत्येक प्रतिभा का सम्मान तथा उसके लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जन–जन की आत्मनिर्भरता से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भारत को विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बना रहा है। राम जन्म भूमि पर भव्य राममंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बाबा महाकाल का दरबार, केदारनाथ सहित सभी तीर्थ क्षेत्रों के विकास से भारतीय संस्कृति के भव्य व दिव्य रूप से विश्व आलोकित हो रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों ने भारत को विश्व की पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना दिया है। देश संतुष्टिकरण अर्थात सबके विकास की नीति पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा सरकार ने सुशासन तथा सख्त कानून व्यवस्था से भय के वातावरण को समाप्त कर प्रदेश में मां, बहन, बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित की है। व्यापारी तथा व्यापार निर्भय हुआ है। डबल इंजन की सरकार तेज गति से प्रदेश का विकास कर रही है।

अराजकता की प्रतीक : पंजाब आम आदमी सरकार

पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण राज्य के लोगों में भय और आशंका का माहौल है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार लोगों में बढ़ती हताशा के बीच अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के फर्जी आंकड़े पेश कर रही है। पंजाब में कुछ ही समय में डकैती की तीन बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। लुधियाना में 10 जून को हुई एक घटना में अपराधियों ने 8.5 करोड़ रूपये और एक दिन बाद अमृतसर में 10.5 लाख रूपये लूट लिए थे। इसके बाद मोगा में एक ज्वैलर्स की दुकान पर हत्या और लूट की घटना का खुलासा हुआ। राज्य की वर्तमान स्थिति पंजाब पुलिस के खराब प्रदर्शन को दर्शाती है, जिसने उग्रवाद से लड़ने में एक सराहनीय भूमिका निभाई थी, लेकिन अब आप सरकार द्वारा हर मोर्चे पर अपनी विफलताओं को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

पंजाब की जेलं अपराधियों और शार्प शूटरों के लिए खेल का मैदान बन गई हैं। पंजाब में कानूनी कार्यवाही निलंबित की जा रही है। इस संबंध में हर राजनेता से तत्काल हस्तक्षेप और ध्यान देने की सख्त जरूरत है। पंजाब को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि 'आप' सरकार ने जेलों को खूंखार अपराधियों के चैनल स्टूडियो में तब्दील कर दिया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल के हाई सिक्योरिटी सेल से मीडिया को इंटरव्यू देने में कामयाब रहा। जेलों से लॉरेंस बिश्नोई के साक्षात्कार से पता चलता है। कि पंजाब में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। कोइ्र आसानी से साबित कर सकता है कि राज्य भर में अपने गिरोह को चलाने के लिए कैदियों के जेल के कमरे में जन संचार उपकरण हैं। पंजाब में फिरौती का धंधा फल–फूल रहा है। अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जेल की कोटरियों में बंद गैंगस्टरों की सभी पहुंच से पता चलता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में एक साल से अधिक समय तक अपना कार्यकाल पूरा करने वाले भगवंत मान न केवल विफल हैं, बल्कि एक प्रशासक के रूप में बेबस नजर आ रहे हैं। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि पंजाब अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य है। पाकिस्तान ने 1980 के दशक में आतंकवाद को प्रायोजित कर पंजाब में भारत के साथ असफल छदम युद्ध छेड़ा था, जिसकी यादें आज भी ताजा हैं।

शोधकर्ताओं और जांज एजेंसियों द्वारा भी यह अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान पंजाब में भारत के साथ ड्रोन और अन्य माध्यमों से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी कर छद्म युद्ध छेड़ रहा है। यह भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत से बदला लेने के लिए खालिस्तानी एजेंडे के साथ प्रवासी पंजाबियों को कट्टरपंथी बनाने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रहा है। आप को पंजाब की पृष्ठभूमि और परिप्रेक्ष्य को जानना चाहिए। आप के राष्ट्रीय सह संयोजक अरविंद केजरीवाल

तरूण चुग

लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और पंजाब की चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। फिर भी यह चिंताजनक है कि केजरीवाल ने मान को राज्य प्रशासन के दिन–प्रतिदिन के कामकाज से दूर रहने दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान चरणजीत सिंह खन्नी के मुख्यमंत्री रहते हुए सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद भी मान सरकार शीर्ष अधिकरियों के खिलाफ सख्त कार्यवाई करने में विफल रही। यह पुलिस के लिए एक निराशाजनक स्थिति थी, क्योंकि वे निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह विचार कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है और किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, सषस्त्र गैंगस्टरों और कुख्यात अपराधियों को प्रोत्साहित करता है। धमकी भरे फोन उद्योगपति और व्यवसायी को लगातार डरा रहे हैं। रंगदारी का धंधा दिन व दिन जोर पकड़ता जा रहा है। इससे पता चलता है कि पंजाब के उद्योगपति निवेश के अवसरों की तलाश में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पंजाब का राज्स्व भी घटा है। इससे पता चलता है कि पंजाब की लचर कानून व्यवस्था भी राज्य की अर्थव्यवस्था को पतन की ओर धकेल रही है। यही वजह है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पंजाब के युवाओं में है। पंजाब का अपना कर राजस्व 2011–12 के 71.82 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 47.79 प्रतिशत हो गया है। यह आंतरिक रूप से संसाधन जुटाने की राजय की क्षमता में स्पष्ट गिरावट को दर्शाता है, जबकि पंजाब अब कर्ज के साथ–साथ केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर है। पंजाब के भीतर संसाधनों का कम जुटना भी इंगित करता है कि खराब कानून और व्यवस्था की स्थिति का वित्तीय स्थिति स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा हे। वहीं, पंजाब की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रशासनिक रिकॉर्ड वाले राज्यों से पिछड़ रही है। जबकि चालू वित्त वर्ष में राज्य जीडीपी विकास दर नाममात्र की दर से 9.5 प्रतिशत अनुमानित है, वही वृद्धि दर उत्तर प्रदेश के लिए 19 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि असम के लिए यह 15 प्रतिशत है। राज्य सरकार का गिरता राजस्व भी पंजाब को कर्ज की ओर धकेल रहा है।

1. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए पंजाब के जीएसडीपी प्रभावी बकाया ऋण 46.81 प्रतिशत होने का अनुमान है। 2. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए पंजाब के जीएडीपी प्रभावी बकाया ऋण का अनुमान 45.23 प्रतिशत था। 3. पंजाब का बकाया कर्ज (बजट अनुमान– 2023–24): 347542.39 करोड़ रूपये। 4. 2022–23 में चुकाया गया कर्जः 30,046 करोड़ रूपये । 5. 2022–23 के लिए उधार (बजट): 55,051 करोड़ रूपये। 6. 2023–24 में चुकाया जाने वाला कर्ज : 38626 करोड़ रूपये। 7. 2023–24 के लिए उधार (बजट) : 94410 करोड़ रूपये।

इससे साफ है कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की भारी कीमत चुकाने के लिए पंजाब और कर्ज ले रहा है।

समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता अपरिहार्य है। यह राष्ट्र राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे आवश्यक बताया है। मोदी ने समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की जरूरत बताते हुए कहा कि, ''इसके नाम पर कुछ दल मुस्लिमों को भड़का रहे हैं।'' उन्होंने इसके विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि, ''एक घर एक परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग कानून हों तो वह परिवार कैसे चल पाएगा?'' उन्होंने याद दिलाया कि, ''सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की थी। लेकिन वोट बैंक राजनीति करने वाले इसका विरोध कर रहे हैं।'' आखिरकार विश्वास आधारित सांप्रदायिक समूहों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का कर्तव्य (अनुच्छेद 44) राष्ट्र राज्य को सौंपा है। समान सिविल संहिता राष्ट्रीय एकता के लिए भी अनिवार्य है। राष्ट्र राज्य का यह कर्तव्य संविधान का भाग है और महत्वपूर्ण नीति निदेशक तत्व है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि, ''नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।'' यह कर्तव्य महत्वपूर्ण है। इसे प्रवर्तित करना राष्ट्र राज्य का कर्तव्य है।

विधि आयोग ने हाल ही में समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगे हैं। लगभग साढ़े आठ लाख सुझाव आए हैं। विधि आयोग का यह कार्य प्रशंसनीय है। लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे नरेन्द्र मोदी सरकार का ध्रुवीकरण एजेंडा बताया है। कांग्रेस की अपनी स्थाई नीति तुष्टिकरण है। ध्रुवीकरण का आरोप इसी का विस्तार है। संवैधानिक कर्तव्य को ध्रुवीकरण बताना संविधान विरोधी है। कांग्रेस दीर्घ काल तक सत्तारूढ़ रही है। उसने कर्तव्य पालन नहीं किया। उसे बताना चाहिए कि उसने समान सिविल संहिता लागू करने के संवैधानिक कर्तव्य पालन की दिशा में क्या कदम उठाए? संहिता लागू करने में कठिनाई क्या थी?

समान नागरिक संहिता बहुत पहले से ही राष्ट्र की वरीयता रही है। सांप्रदायिक निजी कानून महिला अधिकारों और सशक्तिकरण में बाधा है।

हृदयनारायण दीक्षित

समान नागरिक संहिता बहुत पहले से ही राष्ट्र की वरीयता रही है। सांप्रदायिक निजी कानून महिला अधिकारों और सशक्तिकरण में बाधा है। एक समान संहिता संविधान सभा का केन्द्रीय विचार था। संविधान के इस प्राविधान पर सभा (23 नवंबर 1948) में तीखी बहस हुई थी। समान नागरिक संहिता के सभी पहलुओं पर विचार हुआ था। मोहम्मद इस्माइल ने कहा था कि, ''देश में समन्वय के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि लोगों को उनके निजी कानून छोड़ने के लिए बाध्य किया जाए।'' महमूद अली बेग ने कहा था कि, ''हिन्दुओं में विवाह एक संस्कार होता है। यूरोप में यह स्थिति भिन्न है। मुसलमानों में कुरान के अनुसार संविदा जरूरी है। ऐसा नहीं किया जाता तो विवाह वैध नहीं होगा। मुसलमान 1350 वर्षों से इस कानून पर चलते रहे हैं। यदि विवाह की कोई अन्य प्रणाली बनाई जाए तो हम उसे मानने से इंकार कर देंगे।'' नजीरुद्दीन अहमद ने कहा कि, ''प्रत्येक धार्मिक समुदाय के विशेष धार्मिक कानून व विशेष व्यवहार विषयक कानून भी होते हैं। धार्मिक विश्वासों व आचरण से उनका सम्बंध होता है। एक विधि बनाते समय इन धार्मिक कानूनों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। संप्रदाय विशेष के धार्मिक कानूनों को उस संप्रदाय की

सहमति के बिना नहीं बदला जा सकता।'' कुछ सदस्यों ने समान नागरिक संहिता को अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अन्याय बताया।

के०एम० मुंशी ने कहा कि, ''संहिता को अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय बताया जा रहा है। किसी भी उन्नत मुस्लिम देश में अल्पसंख्यक जाति के निजी कानूनों को इतना अटल नहीं माना जाता कि समान नागरिक संहिता बनाने का निषेध हो। तुर्की अथवा मिस्र में किसी अल्पसंख्यक को ऐसे अधिकार नहीं दिए गए।'' कुछ हिन्दू भी समान नागरिक संहिता नहीं चाहते। उत्तराधिकार आदि के निजी कानून उनके धर्म का भाग हैं। इस तरह आप महिलाओं को समानता नहीं दे सकते।'' मुंशी ने मुसलमानों से कहा कि, ''पूरे देश के लिए एक समान संहिता क्यों न हो? मुस्लिम मित्र समझ लें कि जितना जल्दी हम अलगाववाद की भावना को भूल जाएंगे। उतना ही देश के लिए अच्छा होगा।'' राष्ट्र तमाम स्वतंत्र साम्प्रदायिक समूहों का जोड़ नहीं होते। अलगाववाद राष्ट्रीय एकता में बाधा है। फिर यहाँ पूरे देश में एक ही दण्ड विधि प्रवर्तित है।

अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर ने याद दिलाया कि ''जब अंग्रेजों ने इस देश पर अधिकार किया तब उन्होंने कहा था कि हम इस देश में एक ही आपराधिक कानून बना रहे हैं। यह सभी नागरिकों पर लागू होगा। क्या मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया? वे (दण्ड कानून) कुरान के द्वारा शासित नहीं होते। वरन आंग्ल भारतीय न्याय शास्त्र द्वारा शासित है। किंतु इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई।'' ब्रिटिश राज द्वारा बनाए गए दण्ड कानून इस्लामी शरीय से भिन्न हैं। उनका विरोध नहीं हुआ। लेकिन अपनी सर्वशक्ति संपन्न संविधान सभा द्वारा प्राविधानित समान नागरिक संहिता का विरोध जारी है। यह खेदजनक है और आश्चर्यजनक भी। सभा में डॉ० आंबेडकर ने कहा कि, ''यहाँ दण्ड विधान में एक विधि है। संपत्ति हस्तांतरण कानून भी पूरे देश में लागू है। यह कहने का कोई लाभ नहीं कि मुस्लिम कानून अटल है। 1935 तक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में शरीयत कानून नहीं था। उत्तराधिकार आदि विषयों में हिन्दू कानूनों का अनुसरण होता था। 1937 तक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के अतिरिक्त शेष भारत में भी जैसे संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश), मध्य प्रांत और बम्बई में उत्तराधिकार सम्बंधी हिन्दू कानून मुसलमानों पर लागू था।'' डॉ० आम्बेडकर ने सभी आपत्तियों का जवाब दिया। इसके बाद सभी संशोधन पराजित हो गए। समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव पारित हुआ। अनुच्छेद 44 संविधान का भाग बना। आज इसी निदेश का पालन करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय आवश्यकता से कानून का जन्म होता है। बेशक परंपरा और रीति रिवाज भी राष्ट्रीय उपयोगिता के अनुसार विचारणीय होते हैं। लेकिन संस्कृति राष्ट्र की धारक है। भारत जैसे विशाल देश में इसलिए विविधता के बावजूद सांस्कृतिक एकता है। इसलिए एक समान विधि जरूरी है। राष्ट्रीय एकता के लिए एक समान विधि जरूरी है। विविधता भारत की प्रकृति है और एकता भारतीय जन गण मन की अभीप्सा है। बेशक विविधता की बातें बहुत चलती हैं। लेकिन विविधता में एकता राष्ट्र की प्रकृति है। गोवा में ईसाई पंथ मानने वालों की संख्या काफी है। लेकिन यहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। सभी सम्प्रदायों के लोग मजे से रह रहे हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में विश्व के तमाम पंथिक समूहों के नागरिक रहते हैं। अमरीका में समान नागरिक संहिता लागू है। किसी भी सांप्रदायिक समूह को इससे आपत्ति नहीं है। कांग्रेस अल्पसंख्यकवाद के नाम पर मुसलमानों में भय पैदा करती है। तुष्टिकरण करती है। यह पक्षपात है कि एक समुदाय के निजी कानूनों को संहिताबद्ध कर दिया गया है। लेकिन अन्य समुदायों को निजी कानूनों पर चलने की छूट है। महिलाओं की स्थिति दयनीय है। राष्ट्र निजी कानूनों के आग्रही सांप्रदायिक समूहों का गठजोड़ नहीं होते। राष्ट्र सभी नागरिकों में जय पराजय की समान अनुभूति और समान इतिहास बोध व समान नागरिक कानूनों से शक्तिशाली बनते हैं। अब समान नागरिक संहिता लागू करने का यही सही समय है। इस विषय पर देश के प्रत्येक क्षेत्र से यही मांग उठ रही है। इसे अब और टाला नहीं जा सकता। साम्प्रदायिक तुष्टिकरण के लिए विधि आयोग ने सुझाव मांगे हैं। समान नागरिक संहिता की मांग का स्वागत करना चाहिए।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित : शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इंदिरा गाँधी प्रतिष्ठान में डॉ सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जयंती के उपलक्ष्य में 'जन–स्वाभिमान दिवस' कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि डॉ सोनेलाल पटेल जी के जीवन से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम कर रहे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, उप–मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, उप–मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक, श्री सुरेश खन्ना एवं श्री स्वतंत्र देव सिंह सहित राज्य सरकार में कई मंत्री और भाजपा एवं अपना दल के तमाम बड़े नेता उपस्थित थे।

आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित महसूस कर रहा है। मोदी जी के मार्गदर्शन में आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई, धारा 370 समाप्त हुई, आज देश में विकास की न कहानी लिखी जा रही है।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से मैं अपना दल के संस्थापक डॉ सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे जीवन पर्यंत संघर्ष करते हुए गरीबों–पिछड़ों के जीवन में खुशियाँ लाने में लगे रहे। इस दौरान वे कई बार जेल भी गए, प्रताड़ना भी झेली। अनुप्रिया पटेल जी उन्हीं के बताये रास्ते पर चलती हुई गरीबों और पिछड़े समाज के कल्याण एवं उनके सशक्तिकरण में लगी हुई हैं। अपना दल और अनुप्रिया पटेल जी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जारी विकास यात्रा में सहयोगी हैं और एनडीए की सदस्य हैं।

भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से मैं अपना दल के संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे जीवन पर्यंत संघर्ष करते हुए गरीबों-पिछड़ों के जीवन में खुशियाँ लाने में लगे रहे। वे कई बार जेल भी गए, प्रताड़ना भी झेली लेकिन अपने रास्ते से डिगे नहीं।

उत्तर प्रदेश में हमने साथ मिल कर उत्तर प्रदेश में चार चुनाव, दो लोक सभा और दो विधान सभा चुनाव साथ मिल कर लड़े हैं और मिलकर जीते हैं। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी जैसे विघटनकारी पार्टी से उत्तर प्रदेश को निजात मिली है। यूपी में डबल इंजन की सरकार में कानून– व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में औद्योगिक निवेश हो रहा है। गरीब–कल्याण नीतियों और योजनाओं को उत्तर प्रदेश में एनडीए सरकार बखूबी जमीन पर उतार रही है। मैं अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि 2024 के आगामी लोक सभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिल कर उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को विजयी बनाना है।

बीते 9 साल में देश केलगभग 60 करोड़ गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, दलितों और पिछड़े समाज के लोगों के जीवन को ऊपर उठाने काम हुआ है। आजादी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी

के नेतृत्व में यह पहली मंत्रीपरिषद् है जिसमें पिछड़े समाज से लगभग 27 प्रतिशत मंत्री बने हैं और वे सब पिछड़ा समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आज एनडीए गठबंधन में पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज और दलित समाज के सबसे अधिक सांसद हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कई बार गठबंधन में सत्ता में रही लेकिन कभी भी पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। उन लोगों ने कभी भी दलित और आदिवासी आयोग की तरह पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया। ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं जिन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी जिससे पिछड़ा समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सरकार ने एमबीबीएस और एमडी की प्रवेश परीक्षा में पिछड़ा समाज के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया है। ओबीसी छात्रों का ट्यूशन फी भी माफ़ किया गया है। नीट परीक्षा में आरक्षण दिया गया है। पेट्रोल एवं गैस एजेंसियों में भी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। ओबीसी की प्री–मैट्रिक और पोस्ट–मैट्रिक सहायता के लिए अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में दिया गया। ओबीसी समाज के उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल का बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आजमगढ़ मे महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की स्थापना की। डॉ सोनेलाल जी के नाम से प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। यूपी विश्वकर्मा श्रम योजना के तहत लगभग 68 हजार शिल्पियों को लगभग 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। योगी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में अब तक सबसे अधिक पिछड़ा समाज को नौकरी दी गई है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनते ही श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार गरीबों, किसानों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, शोषितों, वंचितों, युवाओं और महिलाओं की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वादे करते हैं, उसे पूरा करते हैं। पिछले नौ साल में भाजपा–एनडीए सरकार ने लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों के लिए आवास बनाए हैं। लगभग 9.5 करोड़ गरीबों के घर में गैस का सिलिंडर पहुंचाया गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.75 करोड़ गैस कनेक्शन वितरित किये गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों का कल्याण हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 11 करोड़ किसानों को हर साल 6–6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को पिछले तीन सालों से प्रति व्यक्ति प्रति महीने पांच किलो अनाज मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश लगभग 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। जब देश में सोनिया–मनामोहन की सरकार थी, तब आए दिन आतंकवादी हमारे देश में घुसकर बम धमाके करते थे, सीमा पर अतिक्रमण करते थे और हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाते थे। श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में भी आतंकवादियों ने वैसी ही हिमाकत करने की कोशिश की लेकिन वे भूल गए कि देश में अब मनमोहन सिंह सरकार नहीं, मोदी जी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे वीर जवानों ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया किया। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज देश सुरक्षित महसूस कर रहा है। देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है, धारा 370 का उन्मूलन हुआ है और देश में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है।

यूपी में डबल इंजन की सरकार में कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में औद्योगिक निवेश हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गरीब-कल्याण नीतियों और योजनाओं को उत्तर प्रदेश में एनडीए सरकार बखूबी जमीन पर उतार रही है।

आजादी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह पहली मंत्री परिषद् है जिसमें पिछड़े समाज से लगभग 27%मंत्री बने हैं। एमबीबीएस और एमडी की प्रवेश परीक्षा में पिछड़ा समाज के लिए 27% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एनडीए गठबंधन में पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज और दलित समाज के सबसे अधिक सांसद हैं।

मजहब के नाम पर पसमांदा

मुसलमानों का शोषण बंद हो !

भारत के अस्सी प्रतिशत मुसलमानों को अब कार्ल मार्क्स वाला वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त बड़ा नीक लग रहा होगा। डेढ़ सदियों से वे सब अमीर–कुलीन मुसलमानों द्वारा शोषण के शिकार होते रहे हैं। बैरिस्टर मुहम्मद अली जिन्ना ने उनकी पिछली पीढ़ी को ठगा था। ऑल–इंडिया मुस्लिम लीग के नाम पर। जिन्ना खुद तो इस्लामी पाकिस्तान के सुल्तान बन बैठे।

भारत में जवाहरलाल नेहरू की भांति। जिन्ना ने इसका बखूबी फायदा उठाया। भारत को तकसीम करके। शेष सबको हिंदू हुकूमत तले छोड़ गए। नेहरू के रहम और दया के सहारे। अब इन शोषित, वंचित, सताये हुए मुसलमानों में वर्ग चेतना आई है। वे मार्क्स की बात समझ गए कि "मजहब अफीम है, जो सिर्फ सरमायेदारों और ताल्लुकेदारों का नायाब हथियार है।"

विभाजन के 75 वर्ष बाद भारत की मुस्लिम आबादी के अस्सी प्रतिशत निर्धन जन ने देर से महसूस किया कि पहले जिन्ना ने उनको झांसा दिया था। तो अब भारत के अशरफ मुसलमान उनका उत्पीड़न कर रहे हैं।

विभाजन के 75 वर्ष बाद भारत की मुस्लिम आबादी के अस्सी प्रतिशत निर्धन जन ने देर से महसूस किया कि पहले जिन्ना ने उनको झांसा दिया था। तो अब भारत के अशरफ मुसलमान उनका उत्पीड़न कर रहे हैं।

ऐसे अधिकांश पसमांदा मुसलमान आजतक इन अमीरजादे मुसलमानों की कारस्तानी के शिकार रहे। वे अधिकतर बाल काटने (नाई), जूतों की सिलाई व साइकिल पंचर बनाने और अंडा बेचने मे रह गए। उन्हें आम कब्रिस्तान तक में दफनाया नहीं जाता। एक चाल चली गई थी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग ने कि इन गरीब मुसलमानों को हिंदूओं ओबीसी कोटा में जोड़ दिया जाए। इन पसमांदा मुसलमानों ने इसका विरोध किया क्योंकि यह कोटा भी अशरफ (रईस) मुसलमान हथिया लेते। भले ही वे सब अपने को उच्च श्रेणी का मानते हों। इनमें ज्यादातर अपना धर्म बदलकर इस्लाम में आए हैं। वे जिस जाति से आए थे, आज भी उन्हें उसी जाति के माने जाते हैं। भारतीय मुस्लिम भी तीन मुख्य वर्गों और सैकड़ों बिरादरियों में बंटे हुए हैं। उच्च जाति के अशरफ कहे जाने वाले मुस्लिम पश्चिम या मध्य एशिया से हैं। इसमें सैय्यद, शेख, मुगल, पठान आते हैं। भारत में सवर्ण जातियों से मुस्लिम बने लोगों को भी उच्च वर्ग में माना जाता है। इसीलिए मुस्लिमों में भी राजपूत, त्यागी, चौधरी, गौर लगाने वाले लोग मिल जाएंगे। सैयद ब्राह्मण माने जाते हैं। भारत में अरब, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से आए मुसलमान खुद को हिंदुस्तानी मुसलमानों से ऊंचा कहते हैं। वंचित कौम है पसमांदा मुसलमान। यह लोग बहुमत में हैं। सताये और पिछड़े हैं। गत सदी से उनका संघर्ष चला था। क्योंकि अशरफिया मुस्लिमों का ही अरसे से देश की सत्ता पर कब्जा रहा। इसी वजह से आज भी उन्हीं का दबदबा है। आजादी के बाद भी इन्होंने ही

के. विक्रम राव

कौम की अगुआई की। नतीजन पसमांदा मुसलमान राजनीतिक तौर पर हाशिये पर ही रह गए। भारत में नब्बे के दशक में पसमांदा मुसलमानों के दो बड़े संगठन खड़े हुए थे : ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज। दोनों संगठन देशभर में पसमांदा मुस्लिमों के सभी छोटे संगठनों का नेतृत्व करते हैं। मगर कट्टर मुस्लिम मजहबी नेता इन दोनों संगठनों को गैर–इस्लामी कहते हैं।

अशरफिया मुस्लिमों का ही देश के ज्यादातर मुस्लिम संगठनों पर दबाव है। जमात–ए–उलेमा–ए–हिंद, जमात–ए–इस्लामी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इदार–ए–शरिया में भी वे ही लोग कब्जा जमाये हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, उर्दू एकेडमी जैसी सरकारी संस्थाओं में भी अशरफिया मुसलमानों की हिस्सेदारी ज्यादा है। लेखक अली अनवर और मसूद आलम फलाही कि किताबों के मुताबिक, मुस्लिम समाज में जाति आधारित कई परतें हैं। जाति पर ही मुसलमानों में भी हिंदुओं की तरह भेदभाव होता है। नमाज पढ़ते समय मस्जिदों में यह साफ नजर आता है।

तो ये बेचारे पसमांदाजन हैं क्या ? राइन, अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, अल्वी, सलमानी, हलालखोर, घोसी, हवाराती, सैफी, सिद्दीकी, इदरीसी, वनगुर्जर जाति के लोग। हालांकि धार्मिक नेताओं ने उनके इंसाफ मांगने वाले आंदोलन को गैर–इस्लामी करार दिया है। राजनीतिक दृष्टि से पसमांदा समाज के लोग देश के लगभग 18 राज्यों में हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। हर विधानसभा सीट पर इनकी उपस्थिति अच्छी खासी संख्या में है। इनमे करीब 44 जातियां शामिल हैं। यह वोट बैंक लोकसभा की सौ से अधिक सीटों पर प्रभावी है।

यूं आमतौर पर हिंदू पार्टी की छवि होने, खासकर बाम्हन, बनिया के कारण, भारतीय जनता पार्टी पर इन पसमांदा मुसलमानों का भरोसा अधिक नहीं है। पर हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अवसरवादी अशरफ (उच्च कोटि के) मुसलमानों के प्रचार जाल में न पड़कर कई पसमांदा मुसलमानों को टिकट दिए। परिणाम अच्छे आए। हालांकि यह कुछ भाजपा नेताओं के लिए मनभावन नहीं था।

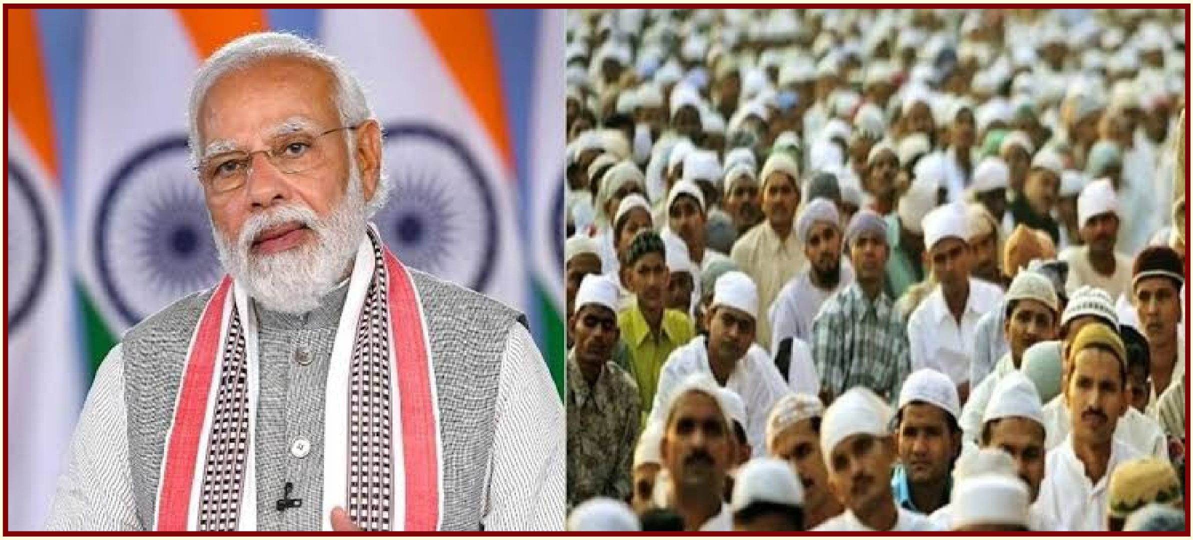

मगर नरेंद्र मोदी ने इतना तो अच्छा किया कि वे उन भाजपाई मुसलमानों, जो बिना जड़ के नेता हैं केवल हिंदू दुलहनियों के पति हैं, को सत्ता की मलाई अब चखने नही दी। उन्हें बरतरफ कर दिया है। मोदी ने इन सर्वहारा मुसलमानों को महत्त्व देने की योजना पर विचार किया है। अर्थात मुसलमान का यह वर्ग संघर्ष तेज करेगा।

अतः बहुसंख्यक हिंदुओं को गहन मंथन करके निर्णय लेना चाहिए कि उनकी हमदर्दी इन शोषित, पसमांदा जन के लिए है या स्वार्थी, अवसरवादी उच्च इस्लामी तबके के पक्ष में ?

प्रगति पर विकास यात्रा

योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में सहभागी हुए। इनके माध्यम से उन्होंने संगीत,संस्कृति और सुरक्षा का संदेश दिया। इन तीनों ही क्षेत्रो में विगत छह वर्षो में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने गोरखनाथ धाम में सावन के प्रथम दिन रुद्राभिषेक किया। उसके पहले उन्होंने राप्ती नदी की आरती उतारी। इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति का संदेश दिया। नदियों के प्रति आदर भाव वस्तुतः पर्यावरण संरक्षण के प्रति दायित्व बोध कराता है। इसी विचार के चलते नमामी गंगे परियोजना सफल हुई। योगी आदित्यनाथ राप्ती नदी के तट गुरु गोरक्षनाथ घाट पर ऊँकारम् संस्था द्वारा आयोजित गुरु गोरक्षनाथ महोत्सव में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने संगीत कला को आगे बढ़ाने के लिए भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ को अत्यन्त दक्षता और स्वच्छ स्पर्धा के साथ आगे बढ़ाया है। आजमगढ़ में हरिहरपुर गांव में संगीत महाविद्यालय स्थापित हो रहा है। यह संगीत महाविद्यालय स्थानीय कलाकारों को डिग्री प्रदान करने के साथ ही एक सार्थक मंच प्रदान करेगा। ऊँकारम् संस्था के संरक्षक भजन सम्राट अनूप जलोटा है। योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा सम्बन्धी संदेश भी दिया। गोरखपुर में गोरखनाथ एवं थाना एम्स के प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण किया। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को सर्वाधिक महत्व दिया।

पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही उन्होंने यह कार्य प्रारंभ कर दिया था। इस सम्बन्ध में योगी मॉडल आज देश दुनिया में प्रसि़द्ध है। छह वर्षो में उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा पूरी तरह बदल गई है। प्रदेश की छवि में व्यापक और सकारात्मक सुधार आया है। योगी ने कहा कि छह वर्ष पहले तक प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं थी. ऐसे में आमजन की सुरक्षा कैसे हो सकती थी। आज प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है। इस माहौल से विकास की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ी है। रूल आफ लॉ सुशासन की पहली शर्त है। आज उत्तर प्रदेश में सभी पर्व और त्योहार शान्तिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं।

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन के लिए प्रदेश पुलिस द्वारा मिशन शक्ति का विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसमें विभिन्न विभाग सहयोग कर रहे हैं। महिला पुलिस कर्मी पंचायत स्तर तक जाकर महिलाओं की समस्याएं सुन रही हैं। उनकी काउंसलिंग तथा समस्याओं का समाधान कर रही हैं। इसके बेहतरीन परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। धर्मांतरण संगठित अपराध व गोवध रोकने के कानूनों को सख्त बनाया गया है।

इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में न्यू आनन्दलोक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो ट्रॉमा सेण्टर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के पचास करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इससे गरीबों को उपचार की बड़ी सुविधा उपलब्ध हुई है।

छह वर्ष पूर्व तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के रूप में एक मात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज था। आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के साथ कार्य कर रहा है। यहां का बाल संस्थान भी बनकर तैयार हो गया है जो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। गोरखपुर में एम्स भी अपना कार्य प्रारम्भ कर चुका है। 'एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज' योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज शुरू करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ हो चुका है। कुशीनगर एवं महराजगंज में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। सिद्धार्थनगर और बस्ती में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है। मेडिकल कॉलेज बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के साथ–साथ मेडिकल की शिक्षा के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। छह वर्ष पहले तक प्रदेश में मात्र बारह राजकीय मेडिकल कॉलेज थे। विगत छह वर्षों में उनसठ नये मेडिकल कॉलेज का निर्माण या तो पूरा किया जा चुका है या किया जा रहा है। शेष सोलह जनपदों में से चार जनपदों में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। असेवित छह अन्य जनपदों के मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्य योजना आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा।

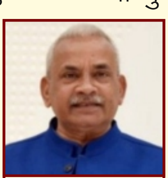

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

स्वत्व और स्वाभिमान से स्वयं को प्रकाशित होने का संदेश है गुरु पूर्णिमा

गुरु पूर्णिमा अर्थात अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर की और यात्रा और व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक स्वाभिमान जाग्रत कराने वाले परम् प्रेरक के लिये नमन् दिवस। जो हमें अपने आत्मबोध, आत्मज्ञान और आत्म गौरव का भान कराकर हमारी क्षमता के अनुरूप जीवन यात्रा का मार्गदर्शन करें वे गुरु हैं। वे मनुष्य भी हो सकते हैं, और कोई प्रतीक भी।

संसार में कोई अन्य प्राणी भी, ज्ञान दर्शन कराने वाला कोई दृश्य, कोई घटना, कोई ग्रंथ या ध्वज जैसा भी कोई प्रतीक हो सकता है। अपने ज्ञान दाता के प्रति आभार और उनके द्वारा दिये गये ज्ञान से स्वयं के साक्षात्कार करने की तिथि है गुरु पूर्णिमा।

आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने का भी एक रहस्य है। भारत में प्रत्येक तीज त्यौहार के लिये तिथि का निर्धारण साधारण नहीं होता, प्रत्येक तिथि का अपना संदेश होता है। गुरु पूर्णिमा की तिथि का भी एक संदेश है। इसका निर्धारण एक बड़े अनुसंधान का निष्कर्ष है।

वर्ष में कुल बारह पूर्णिमाएँ आतीं हैं। इन सभी में केवल आषाढ़ की पूर्णिमा ऐसी है जिसमें चंद्रमा का शुभ प्रकाश धरती पर नहीं आ पाता। या सबसे कम आता है। वर्षा के बादल चंद्रमा के प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। एक प्रकार से चंद्रमा को ढंक लेते हैं। शुभ्र चंद्र–प्रकाश तो धरती पर आने का प्रयत्न तो करता है पर बादल अवरोध बन जाते हैं।

यदि गुरु का संबंध केवल ज्ञान और प्रकाश से होता तो अश्विनी मास की शरद पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा माना जा सकता था। चूँकि इस पूर्णिमा को धरती पर आने वाला चन्द्र प्रकाश सबसे धवल और मोहक होता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा माना गया। इसका संदेश ज्ञान पर आनी वाली भ्रान्तियों को दूर करना है। आषाढ़ की पूर्णिमा पर चन्द्र प्रकाश को रोकने वाले बादल स्थाई नहीं होते, वह अवरोध मौलिक नहीं होता, कृत्रिम होता है, अस्थाई होता है, जो समय के साथ छंट जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य की आँखो पर अज्ञान के बादल छाये रहते हैं। भीतर आत्मा तो परमात्मा का अंश है, जो ज्ञान और प्रकाश का पुंज है। पर मनुष्य का अज्ञान, अशिक्षा और भ्रांत धारणाओं की परतें आत्मा को ढक लेती हैं। जिससे मनुष्य की प्रगति अवरुद्ध होंने लगती है और उसके कुमार्ग पर चलने की आशंका हो जाती है। जिस प्रकार पवन देव बादलों को उड़ा ले जाते हैं धरती और चन्द्रमा के बीच का अवरोध समाप्त कर देते हैं, और शुभ्र चंद्र प्रकाश पृथ्वी की मोहक छवि को पुनः उभारने लगता है उसी प्रकार मनुष्य के ज्ञान बुद्धि पर पड़े अवरोध स्वयं नहीं हटते, उन्हे हटाने के लिये कोई प्रयत्न चाहिए, कोई निमित्त चाहिए। जो अज्ञान की परत का क्षय करके स्वज्ञान का भान करा सके। अज्ञान का हरण कर स्वज्ञान के इस जाग्रत कर्ता को ही गुरु कहा गया है। यह गुरु की विशेषता होती है कि अज्ञानता के अंधकार की ये

सभी परतें हटा कर उसे उसके स्वत्व से साक्षात्कार कराता है। मनुष्य की विशिष्ठता को नये आयाम, नयी ऊँचाइयाँ देने में मार्ग दर्शन करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा इसी का प्रतीक है।

शिक्षक और गुरु में अंतर

गुरुत्व परंपरा में एक बात महत्वपूर्ण है। शिक्षक, आचार्य, गुरू और सद्गुरु में अंतर होता है। शिक्षक और आचार्य गुरु तुल्य तो होते हैं पर गुरु नहीं होते। एक तो शिक्षक अस्थाई होते हैं और वे केवल निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार चलते हैं। शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। शिक्षा केवल सैद्धांतिक होती है। यदि पाठ्यक्रम में कुछ असत्य है आधारहीन है तब भी षिक्षक उसी अनुसार अपना कार्य करते हैं। जबकि आचार्य इस पाठ्यक्रम में व्यवहारिक पक्ष को भी सम्मिलित कर व्यक्तित्व निर्माण पर भी ध्यान देते हैं। लेकिन गुरु इनसे बहुत आगे हैं। वे गुरु पहले शिष्य की प्राकृतिक प्रतिभा क्षमता रुचि का आकलन करते हैं, उसकी मौलिक प्रतिभा को जाग्रत करते है। फिर उसके अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीनों थे तो एक ही कक्षा में पर गुरु द्रोणाचार्य ने तीनों को उनकी प्रतिभा और क्षमता के अनुरूप अलग–अलग अस्त्र शस्त्र में प्रवीण बनाया। गुरू सदैव अपने शिष्य की रुचि और प्राकृतिक क्षमता को ध्यान में रखाकर शिक्षा और ज्ञान दोनों का निर्धारण करता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से केवल चेहरे की बनावट, बोली, रुचि, पसंद नापसंद या डीएनए में ही अलग नहीं होता। वह प्राकृतिक विशेषताओं में भी पूरी तरह अलग होता है, विशिष्ट होता है। प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्रतिभा में विशिष्ट बनाया है। व्यक्ति की यह मौलिक प्रतिभा क्या है, क्षमता क्या है, मेधा क्या है और प्रज्ञा कैसी है। इसका आकलन गुरु करते हैं। और उस व्यक्ति को उसके मूल तत्व का आभास कराते हैं, उसके स्वत्व से साक्षात्कार कराते हैं। जिससे वह अपने जन्म जीवन को योग्य बनाता है। और सद्गुरु।

गुरु केवल लौकिक जगत के ज्ञान विज्ञान तक रहते हैं। एक शिष्य संसार में कैसे श्रेष्ठ बने, संसार में कहाँ क्या है। संसार की प्रकृति, प्राणी और पदार्थ सबसे कैसे तादात्म्य स्थापित हो यह सब ज्ञान गुरु देते हैं। लेकिन सद्गुरु लौकिक और अलौकिक दोनों का मार्ग दर्शन कराते हैं। संसार के आगे क्या है ? दृश्य जगत के आगे अदृश्य की शक्ति क्या है। यह ज्ञान सद्गुरु से मिलता है। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य हैं। पर जब योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया तब अर्जुन ने कहा– "मुझे सद्गुरु की भाँति उपदेश करें" और तब ही भगवान श्रीकृष्ण ने विभूति और विराट से परिचय कराया।

इस प्रकार संसार में जीने योग्य बनाने, सफलता प्राप्त करने, लौकिक जगत को समझने और अलौकिक जगत का साक्षात्कार कराने वाली विभूति को गुरु कहा गया और उनके प्रति आभार प्रकट करने की तिथि है गुरु पूर्णिमा।

गुरु पूजन की परंपरा

इस दिन शिष्य अपने गुरु की अभ्यर्थना करते हैं, वंदना करते हैं। यह एक प्रकार का पूजन है। गुरु पूजन की यह परंपरा कब से आरंभ हुई यह नहीं कहा जा सकता है। भारतीय वाङ्मय में पीछे जितनी दृष्टि जाती है वहाँ गुरु परंपरा के आख्यान मिलते हैं। परम् गुरु भगवान् शिव को माना गया है। आदि गुरु महर्षि कश्यप, महर्षि भृगु, देव गुरु बृहस्पति और

दैत्य गुरु शुक्राचार्य माने गये हैं। इसके बाद विभिन्न ऋषियों राजकुलों के गुरु के रूप में उल्लेख मिलता है। राजकुलों में बीच–बीच में गुरु बदले भी हैं। यह वर्णन भी पुराणों में है। पौराणिक आख्यानों में केवल गुरु परंपरा का ही उल्लेख नहीं अपितु ऋषियों की ज्ञान सभा होने के भी उल्लेख है।

आरंभिक काल में ऐसी ज्ञान सभाएं शिव निवास कैलाश पर्वत पर होती थीं। जिनमें ऋषिगण भाग लेते थे, वे शिवजी के सामने समाज की स्थिति का चित्रण करते थे फिर भगवान् शिव समाधान सूत्र दिया करते थे। इसके बाद ऐसी ज्ञान सभाएं काशी में होने लगीं। ये सभाएं भी शिवजी के सभापतित्व में ही होतीं थीं। इसलिये भगवान शिव को ही आदि गुरु या परम् गुरु कहा गया है। आगे चलकर इन समाजों का केन्द्र नैमिसारण्य बना। यहाँ आचार्य प्रमुख महर्षि भृगु थे और यहीं से सभापतित्व का दायित्व ऋषियों के हाथ में आया।

इन सभाओं का सप्त ऋषियों में से कोई अथवा उनके द्वारा आमंत्रित कोई अन्य प्रमुख ऋषि द्वारा सभापतित्व करने की परंपरा आरंभ हुई। ये सभाएं चतुर्मास की पूरी अवधि में हुआ करतीं थीं जो आषाढ़ की पूर्णिमा से आरंभ होकर शरद पूर्णिमा तक निरंतर चला करतीं थीं। इसलिये आज भी गुरु परंपरा के प्रत्येक संत इस अवधि में अपने मूल आश्रम में ही निवास करते हैं।

नेमीसारण्य की इस ज्ञान सभा परंपरा के शिथिल होंने के बाद क्षेत्रीय सभाओं की परंपरा आरंभ हुई और इसी के साथ स्थानीय स्तर पर गुरु वंदन पूजन आरंभ हुआ। यद्यपि शंकराचार्य पीठ, महामंडेश्वर पीठ आदि प्रमुख गुरु स्थानों पर आज भी चतुर्मास में निरंतर व्याख्यान होने की परंपरा हो।

पुराणों में आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु महत्ता स्थापना की पहला विवरण त्रेता युग के आरंभ में मिलता है। इसी तिथि को भगवान् शिव ने नारायण के अवतार भगवान् परशुराम जी को शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। भगवान् शिव के भक्त तो सभी हैं पर शिष्य अकेले परशुराम जी, और इसी तिथि से भगवान् अमरनाथ के दर्शन आरंभ होने परंपरा भी बनी। वशिष्ठ परंपरा में इस तिथि को महर्षि व्यास का जन्म हुआ, जिन्होंने वेदों का भाष्य तैयार किया। इस प्रकार इस तिथि का महत्व बढ़ता गया।

गुरु के प्रतीक : प्राणी, प्र ति, ग्रंथ और ध्वज

आरंभिक काल में गुरु परंपरा के वाहक अधिकांश ऋषिगणों का उल्लेख मिलता है, पर समय के साथ इसका विस्तार हुआ। गुरु केवल ऋषि ही बनें अथवा जीवन में केवल एक ही गुरु हों यह बंधन कभी नहीं रहा। एक से अधिक गुरु और ऋषियों से इतर किसी प्रतीक या घटना को भी गुरु मानने की परंपरा रही है। यहाँ तक कि पशु पक्षी और सेवक के अतिरिक्त कोई प्रतीक जैसे यज्ञ, ग्रंथ और ध्वज को भी गुरु का मानने की परंपरा आरंभ हुई।

भगवान् दत्तात्रेय जी के चौबीस, भगवान् परशुराम जी के सात और राजा जनक के तीन गुरु होने का वर्णन मिलता है। भगवान् दत्तात्रेय की चौबीस गुरु संख्या में पृथ्वी, जल, अग्नि आकाश भी हैं। उन्होंने मधु मक्खी, श्वान् आदि उन पशु पक्षियों को भी अपना गुरु माना जिनसे उन्होंने कार्य संकल्प की सीख लेने का संदेश दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने पिता महर्षि भृगु के साथ यज्ञ को भी गुरु माना। राजा जनक के तीन गुरु संख्या में प्रतीक के रूप में वेद भी गुरु हैं आगे चलकर राजा जनक ने अन्य राजाओं को वेदज्ञान दिया ऋषिका देवहूति ने अपने पुत्र कपिल मुनि को गुरु रूप में स्वीकारा तो ऋषि कहोड़ ने अपने पुत्र अष्टावक्र को गुरु समान आदर दिया।

आदि शंकराचार्य जी ने एक चाँडाल को गुरु समान आदर दिया और पंचकम् की रचना की। स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी की नृत्यांगना को माँ कहकर पुकारा और गुरु का सम्मान दिया। इसी परंपरा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने "ध्वज" को गुरु रूप में स्वीकारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवक गुरु पूर्णिमा पर ध्वज का ही पूजन करते हैं। संघ की स्थापना के तीन वर्ष बाद ध्वज पूजन की यह परंपरा आरंभ हुई। भारत में यह ध्वज पूजन परंपरा पहली नहीं है। भारत में अनादि काल से ध्वज को सम्मान का प्रतीक माना और इसकी रक्षा के लिये प्राणोत्सर्ग करने की घटनाओं से प्राचीन ग्रंथ भरे पड़े हैं। ध्वज नायक या राज्य की पहचान

का प्रतीक थे, जैसे गरुड़ ध्वज नारायण की, अरुण ध्वज सूर्य की पहचान रहें हैं। ध्वज को राष्ट्र के प्रतीक के रूप में वंदन करने की परंपरा आचार्य चाणक्य के समय आरंभ हुई। आचार्य चाणक्य ने भगवा ध्वज को भारत राष्ट्र की पहचान और मान का प्रतीक प्रमाणित किया। ज्ञान के लिये शब्द और स्वर के साथ प्रतीक भी माध्यम होते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति, परिवार समाज और राष्ट्र संस्कृति के स्वत्व की पहचान का प्रतीक ध्वज होता है।

गरुड़ ध्वज से नारायण और अरुण ध्वज से सूर्य की पहचान होती है उसी प्रकार भगवा ध्वज भारत राष्ट्र की पहचान है। भगवा अग्नि शिखा का रंग होता है, सूर्योदय की आभा ऊषा का रंग होता है जो समता समानता का द्योतक होता है। अग्नि सभी को एकसा ताप देती है। सूर्य सबको समान प्रकाश और ऊर्जा देता है। इसलिए भारत ने अपनी ध्वजा का रंग भगवा स्वीकार किया। स्वाभिमान के जागरण का प्रतीक शब्द 'ध्वज' संस्कृत की "ध्व" धातु से बनता है। इसका आशय धरती की केन्द्रीभूत शक्ति होता है। इसे धारण करने के कारण ही ऋग्वेद में धरती केलिये "धावा" उच्चारण आया है। भगवा ध्वज भारत राष्ट्र का प्रतीक है इसकी कोई राजनैतिक अथवा क्षेत्र विशेष की सीमा नहीं है। यह शिक्षा संस्कार, सात्विकता और स्वाभिमान का प्रतीक है।

भारत ने पूरी धरती के निवासियों को एक कुटुम्ब माना। इसलिए भारत ने कभी भी, किसी भी युग में राजनैतिक या साम्राज्य विस्तार के लिये कोई युद्ध नहीं किया। जो युद्ध हुये वे सुरक्षा के लिये हुये अथवा धर्म, नैतिकता और संस्कृति की रक्षा के लिए हुये वह भी आक्रामक नहीं केवल सुरक्षात्मक। ये युद्ध भी तब हुये जब शाँति के सभी मार्ग अवरुद्ध हो गये। इन युद्धों में सिद्धांत स्वाभिमान के साथ ध्वज का सम्मान सर्वोपरि रहा।

ध्वज भूमि पर न गिरे इसके लिये कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दीं हैं यह हमने दाशराज युद्ध, राम रावण युद्ध, महाभारत युद्ध से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी देखा। ध्वज किसी भी राष्ट्र और संस्कृति के गौरव और सम्मान का प्रतीक माना गया है। इससे आत्मगौरव और स्वाभिमान का भी वोध होता है। यह राष्ट्र और स्वाभिमान वोध ही है जो व्यक्ति को स्वत्व सम्मान की स्थापना के लिये प्रेरित करता है। यह बात आचार्य चाणक्य ने कही थी और इसीको आगे बढ़ाया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डा हेडगेवार ने। उन्होंने कहा था "जो आत्मवोध कराये वह गुरु है, मनुष्य या प्राणी का जीवन तो सीमित होता है। समय और आयु अवस्था उनकी क्षमता और ऊर्जा को प्रभावित करती है, अतएव गुरु चिरजीवी होना चाहिए "।

अष्टावक्र से मिले आत्मज्ञान के बाद इसी भाव के अनुरूप राजा जनक ने वेद को भी गुरु तुल्य आसन दिया। गुरुग्रंथ साहिब को गुरु स्थान का सम्मान देना इसी परंपरा का पालन है।

लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जितनी आवश्यकता आत्मज्ञान की है उससे अधिक आवश्यकता स्वत्व के वोध और राष्ट्र के स्वाभिमान जागरण की है। उधार के सिन्दूर से कोई सौभाग्यवती नहीं हो सकती, वैशाखियों के सहारे कोई पर्वत की चोटी पर नहीं जा सकता उसी प्रकार कोई व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र अपने स्वत्व से दूर होकर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। यह भगवा ध्वज प्रत्येक भारतीय को उसके स्वत्व और स्वाभिमान का वोध कराता है। व्यक्तिगत ज्ञान केलिये किन्हीं ऋषि तुल्य विभूति से दीक्षा लेना आवश्यक है पर राष्ट्र स्वाभिमान जागरण कर्ता के रूप में ध्वज के अतिरिक्त कोई प्रतीक नहीं हो सकता।

आज जीवन की आपाधापी है। भौतिक सुख सुविधाओं के संघर्ष में आत्मगौरव कहीं छूट रहा है। इसके लिये आवश्यक हैं कि गुरु पूर्णिमा पर केवल गुरु वंदन पूजन तक सीमित न रहें। प्रत्येक व्यक्ति कमसेकम एक बार आत्म चिंतन अवश्य करे स्वयं के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में और अपने राष्ट्रगौरव के बारे में। और यदि कहीं चूक हो रही है तो उसकी पुनर्प्रतिष्ठा कैसे की जाये इसका संकल्प लिया जाय तभी गुरु पूर्णिमा पर गुरु वंदन पूजन सार्थक होगी।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

'गीता प्रेस' के सम्मान का विरोध करके क्या प्राप्त होगा?

भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने सर्वसम्मति से गीता प्रेस, गोरखपुर को प्रतिष्ठित 'गांधी शांति पुरस्कार' देने का निर्णय करके बहुत अच्छा काम किया है। इसी वर्ष गीता प्रेस ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किये हैं। अपनी इस 100 वर्ष की यात्रा में इस प्रकाशन ने भारतीय संस्कृति की खूब सेवा की है। भारतीयता के विचार को जन–जन तक पहुँचाने में गीता प्रेस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस आज विश्व के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक मानी जाती है। इस प्रेस ने अब तक 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित कर नया कीर्तिमान बनाया है। इनमें से श्रीमद्भगवद्गीता की 16.21 करोड़ प्रतियां शामिल हैं। गीता प्रेस की नीति के कारण श्रीमद्भगवतगीता, श्री रामायण, श्री महाभारत सहित अनेक भारतीय ग्रंथ घर–घर तक पहुँच सके।

पुरस्कार की घोषणा के बाद गीता प्रेस को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उचित ही कहा– "गीता प्रेस ने पिछले 100 वर्षों में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिशा में काफी सराहनीय कार्य किया है"। आश्चर्य है कि कुछ लोगों/संगठनों को गीता प्रेस को पुरस्कार दिए जाने का निर्णय भी चुभ रहा है। सामान्य लोगों को भी यह समझ आ रहा है कि विरोध के पीछे की मानसिकता क्या है– गीता प्रेस ने हिन्दू धर्म–संस्कृति को जन–जन तक पहुँचाया है, क्या इसलिए उन्हें कष्ट है? देश में कुछ विचार समूह ऐसे हैं, जिन्हें प्रत्येक हिन्दू पहचान एवं भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित संस्थाओं से चिढ़ है।

"गीता प्रेस को 'गांधी शांति पुरस्कार–2021' दिया जाना, सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है"। यह विचार अत्यंत संकीर्ण सोच को प्रकट करता है। इस बेतुके बयान के समर्थन में जिस पुस्तक का जिक्र किया गया है, उसके लेखक को गीता प्रेस और उसके प्रकाशनों के प्रति बुनियादी जानकारी ही नहीं है। पुस्तक 'गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिन्दू इंडिया' में लेखक अक्षय मुकुल ने अनेक बुनियादी बातों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। एक मजेदार तथ्य यह है कि इस पुस्तक की प्रशंसा विवादित लेखिका अरुंधति रॉय ने की है। याद हो, अरुंधति मानवता के दुश्मन खूंखार नक्सलियों को बंदूकधारी गांधीवादी बताती है। इस पुस्तक के आधार पर पूर्व में भी गीता प्रेस की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयत्न किया जा चुका है। इस बात को तथ्यात्मक रूप से समझने के लिए डॉ. संतोष कुमार तिवारी का शोधपूर्ण आलेख 'गीता प्रेस को बदनाम करने की कोशिश' पढ़ना चाहिए, जो 20 मार्च 2017 को पांचजन्य के वेबसाइट पर प्रकाशित है। उल्लेखनीय है कि डॉ. तिवारी ने ब्रिटेन के कार्डिफ विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त की है और वे झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग से प्राध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। विरोधियों की मानसिकता देखिए कि वे गीता प्रेस के

लोकेन्द्र सिंह

सम्मान को स्वातंत्र्यवीर सावरकर और नाथूराम गोडसे से जोड़कर एक यशस्वी प्रकाशन के संबंध में भ्रम और विवाद खड़ा करना चाहते हैं। ओछे राजनीतिक स्वार्थ के चलते स्वातंत्र्यवीर सावरकर के प्रति चिढ़ ने नेताओं को इतना अंधा कर दिया है कि उन्हें इस महान क्रांतिकारी के संबंध में न तो महात्मा गांधी के विचार स्मरण रहते हैं और न ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विचार एवं कार्य। वितंडा खड़ा करने में आनंद लेनेवालों को समझना होगा कि तथ्यों के घालमेल से सच नहीं बदल जाएगा। सच यही है कि गीता प्रेस के प्रति प्रत्येक भारतीय के मन में अगाध श्रद्धा है। गीता प्रेस ने अपनी अब तक की अपनी यात्रा में भारतीय संस्कृति की महान सेवा की है।

विरोधियों द्वारा यह कहना कि महात्मा गांधी और गीता प्रेस के प्रबंधकों के बीच घोर असहमतियां थी– निराधार और मूर्खतापूर्ण कथन है। महात्मा गांधी और गीता प्रेस के संबंध कैसे थे, इसे दो प्रमाणों के आधार पर समझिए। गीता प्रेस की सुप्रसिद्ध पत्रिका 'कल्याण' के पहले अंक में महात्मा गांधी ने लेख लिखा था। इतना ही नहीं, बाद में भी गांधीजी कल्याण के लिए लिखते रहे। दूसरा तथ्य देखिए– पत्रिका के संपादक भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार और प्रबंधन ने महात्मा गांधी के आग्रह को शिरोधार्य करते हुए 'कल्याण' में कभी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए।

गीता प्रेस का अध्ययन करनेवाले विद्वान डॉ. संतोष तिवारी 'पांचजन्य' में 19 जून 2023 को प्रकाशित लेख 'गीताप्रेसः गांधीजी और कल्याण के रिश्ते' में लिखते हैं– "कल्याण के अक्टूबर 1946 के अंक पर एक बार ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया था। जब 'कल्याण' का प्रकाशन दोबारा शुरू हुआ तो श्री पोद्दार बापू से आशीर्वाद लेने गए थे। गांधीजी ने तब उनको यह सलाह दी थी कि कल्याण में कभी भी बाहर का कोई विज्ञापन या पुस्तक समीक्षा मत छापना। 'कल्याण' पत्रिका आज तक गांधीजी के उस परामर्श का अनुसरण करती आ रही है। गीता प्रेस किसी से कोई दान राशि भी स्वीकार नहीं करती है"।

एक अन्य तथ्य भी ध्यान रखिए कि भारत की स्वतंत्रता के संकल्प को शक्ति देने के लिए 'राम–नाम जाप' का आग्रह लेकर जब भाई पोद्दार मुंबई में महात्मा गांधी से मिले थे, तब गांधीजी ने 'राम–नाम' का प्रसार करने के लिए प्रशंसा की थी। वास्तविकता यह है कि महात्मा गांधी के साथ श्री पोद्दार का संबंध एक परिवार के जैसा था। 1932 में गांधीजी के पुत्र देवदास गांधी को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार करके गोरखपुर जेल में रखा था। गांधीजी के कहने पर श्री पोद्दार ने देवदास गांधी का पूरा ख्याल रखा और नियमित रूप से जेल में उनसे मिलते रहे। रिहाई के फौरन बाद जब देवदास गांधी बीमार पड़े, तब भी श्री पोद्दार ने उनका ख्याल रखा। महात्मा गांधी ने 21 जुलाई 1932 को भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार को लिखे पत्र में प्रसन्नता एवं आश्वस्ति व्यक्त करते हुए लिख है– "भाई हनुमान प्रसाद, आज तुम्हारा पत्र मिला और तार भी। तुम जबतक वहाँ हो, तबतक मुझे देवदास की चिंता नहीं रहेगी। और फिर, देवदास ने मुझे लिखा है कि तुमने बहुत स्नेहपूर्ण बर्ताव किया है। डॉक्टर वाकई बहुत अच्छे आदमी हैं। समय–समय पर तुम्हारे पत्र मुझे मिलते रहेंगे, ऐसी मेरी सदैव आशा है" (देखें– संपूर्ण गांधी वाङ्मय (हिन्दी), खण्ड–50, पृष्ठ–274)। कई लोग यह भी झूठ फैलाते हैं कि 'कल्याण' में महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन पर कोई सामग्री प्रकाशित नहीं हुई। वास्तविकता यह है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब 'कल्याण' में दो श्रद्धांजलियां प्रकाशित हुईं, जिनमें से एक स्वयं संपादक भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार ने लिखी थी। अपने संदेश में उन्होंने लिखा– ''गांधीजी धर्म और जाति के भेद से ऊपर उठे हुए थे और सत्य एवं अहिंसा के सच्चे पुजारी थे''।

इसके बाद भी यदि कुछ लोग यह कहकर विरोध में छाती पीट रहे हैं कि महात्मा गांधी का गीता प्रेस के प्रबंधकों एवं संपादक भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार के साथ गहरा मतभेद था, तब वे किस–किस का विरोध करेंगे क्योंकि अनेक मुद्दों पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार भगत सिंह और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर से लेकर अनेक महापुरुषों के साथ गांधीजी असहमतियां रखते थे।

गीता प्रेस का संकल्प देखिए कि उसने आज तक किसी से अनुदान प्राप्त नहीं किया। इसी संकल्प को बनाए रखते हुए गीता प्रेस के प्रबंधकों ने 'गांधी शांति पुरस्कार–2021' को तो स्वीकार किया लेकिन पुरस्कार में मिलनेवाली एक करोड़ रुपये की राशि को स्वीकार करने से मना कर दिया। एक करोड़ रुपये की राशि, बहुत बड़ी राशि है। गीता प्रेस का विरोध करनेवाले गिरोह में ऐसे लोग भी शामिल हैं, जो अवार्ड वापसी समूह का हिस्सा रहे हैं। उस बनावटी अभियान में इन लोगों ने अवार्ड तो लौटाए थे लेकिन उसके साथ मिली राशि को आज तक नहीं लौटाया है।

मोदी स्टोरी

मोदी जी का दिव्यांगजन से वादा

—डॉ. रमापति राम त्रिपाठी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में विकलांग व्यक्तियों के लिए 'विकलांग' के बजाय 'दिव्यांग' शब्द का उपयोग करने का सुझाव दिया था। इस पर कई लोगों का यह मानना हो सकता है कि यह केवल एक अलग शब्द का उपयोग है, लेकिन शब्दों में हर चीज को प्रभावित करने की अनंत शक्ति होती है। हम अब बदलाव देख सकते हैं। यह दिव्यांग लोगों के प्रति प्रधानमंत्री श्री मोदी की करुणा और भाव को भी दर्शाता है।

हालांकि, दिव्यांग लोगों के प्रति प्रधानमंत्री श्री मोदी का रवैया उनके शुरुआती दिनों में भी ऐसा ही था। उनके प्रारंभिक जीवन में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां उन्होंने किसी दिव्यांग व्यक्ति की देखभाल या मदद की। यहां 90 के दशक का एक किस्सा याद आता है, जब श्री मोदी ने एक दिव्यांग से किया वादा पूरा किया।

1999 के आम चुनावों के दौरान श्री नरेन्द्र मोदी पार्टी के काम के लिए लखनऊ आए थे। एक बार वह किसी कार्यक्रम के लिए कार से जा रहे थे। गेट पर एक दिव्यांग खड़ा था। जैसे ही वह गेट पार कर रहा था, पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिव्यांग व्यक्ति को गेट के एक तरफ खड़ा कर दिया और गाड़ी पार हो गई, लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना को देख लिया।

उन्होंने कार रोकी और उसमें से निकलकर उस दिव्यांग शख्स के पास आए। श्री मोदी ने उससे आने का कारण पूछा। दिव्यांग व्यक्ति ने उनसे कहा कि उसे ट्राइसाइकिल की जरूरत है और इसीलिए वह आया है।

श्री नरेन्द्र मोदी के साथ डॉ. रमापति राम त्रिपाठी भी मौजूद थे, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया से लोकसभा सांसद थे।

श्री मोदी ने डॉ. त्रिपाठी की ओर देखते हुए उनसे उस दिव्यांग व्यक्ति के लिए ट्राइसाइकिल की व्यवस्था करने का आग्रह किया। डॉ. त्रिपाठी ने उनसे अपना नाम और पता कार्यालय में लिखवाने को कहा और मोदीजी को उनकी मदद करने का आश्वासन दिया।

इस घटना के दो महीने बाद श्री नरेन्द्र मोदी पुनः लखनऊ गये। एक शाम जब वह नेताओं के साथ पार्टी कार्यों पर चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने डॉ रमापति राम त्रिपाठी से पूछा कि क्या उस दिव्यांग व्यक्ति के लिए ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई गई थी। दरअसल उस घटना के बाद डॉ. त्रिपाठी इस पर फॉलो–अप करना भूल गए थे।

अगली सुबह डॉ. त्रिपाठी उस दिव्यांग व्यक्ति के पास गये और उसे श्री नरेन्द्र मोदी के पास ले गये। डॉ. त्रिपाठी ने मोदीजी से कहा कि यह वह व्यक्ति है और आप देख सकते हैं कि वह ट्राइसाइकिल चला रहा है।

इस घटना के बारे में बताते हुए डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि जब वह इस घटना को भूल गए थे, तब भी श्री नरेन्द्र मोदी को महीनों बाद इसकी याद आई और उन्होंने दिव्यांगों से किया अपना वादा निभाया। इससे पता चलता है कि दिव्यांगों के लिए उनके दिल में कितनी करुणा है।

सरकार की उपलब्धियां

रोजगार मेला सरकार की नई पहचान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 जून को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित किया तथा विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को लगभग 70,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश भर से चयनित युवा वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखा परीक्षण और लेखा विभाग, गृह मंत्रालय आदि विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त होंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान देश भर के 43 स्थानों को मेले से जोड़ा गया था।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय रोज़गार मेला वर्तमान सरकार की नई पहचान बन गया है, क्योंकि आज 70,000 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भाजपा और एनडीए शासित राज्य भी नियमित रूप से इस प्रकार के रोजगार मेले आयोजित कर रहे हैं।

यह देखते हुए कि आजादी का अमृत काल अभी शुरू हुआ है श्री मोदी ने कहा कि यह उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, जो सरकारी सेवा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान के साथ–साथ आपको देश के भविष्य के लिए भी सब कुछ देना चाहिए। श्री मोदी ने इस अवसर पर नवनियुक्त युवाओं और उनके परिवार के सदस्यों को बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था में रोजगार और स्वरोजगार के उभरते अवसरों के बारे में बात की। उन्होंने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब ये युवा नौकरी देने वाले बन रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का अभियान अभूतपूर्व है। एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी जैसे संस्थान नई व्यवस्था के साथ ज्यादा नौकरियां दे रहे हैं। ये संस्थान भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और आसान बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती–अवधि 1–2 साल से घटकर कुछ महीने की रह गयी है।

उल्लेखनीय है कि रोजगार मेला, रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। रोजगार मेले से आगे के रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाने और युवाओं को उनके सशक्तीकरण तथा राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने की उम्मीद की जाती है।

नई शामिल की गई भर्तियों को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का भी एक अवसर प्राप्त हो रहा है, जहां 400 से अधिक ई–लर्निंग पाठ्यक्रम 'कहीं भी किसी भी डिवाइस' सीखने के प्रारूप के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

सरकार की उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह में 12.73% की हुई भारी वृद्धि

वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष करों का शुद्ध संग्रह 11.18% से भी अधिक बढ़ा तथा वित्त वर्ष 2023-24 में 17 जून, 2023 तक अग्रिम कर संग्रह 1,16,776 करोड़ रुपये का हुआ, जो 13.70% की वृद्धि दर्शाता है

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 18 जून को जारी एक बयान के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह (रिफंड के समायोजन से पहले) पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 3,71,982 करोड़ रुपये की तुलना में 4,19,338 करोड़ रुपये का हुआ, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में हुए संग्रह की तुलना में 12.73% की वृद्धि दर्शाता है।

4,19,338 करोड़ रुपये के सकल संग्रह में 1,87,311 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स (सीआईटी) और प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) सहित 2,31,391 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल है। लघु मद वार संग्रह में 1,16,776 करोड़ रुपये का अग्रिम कर; 2,71,849 करोड़ रुपये का टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती); 18,128 करोड़ रुपये का स्व-आकलन कर; 9,977 करोड़ रुपये का नियमित आकलन कर शामिल है और अन्य छोटे मदों के तहत 2,607 करोड़ रुपये का कर संग्रह शामिल है।

वित्त वर्ष 2023-24 में 17 जून, 2023 तक के प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़ों से पता चलता है कि शुद्ध संग्रह 3,79,760 करोड़ रुपये का हुआ, जबकि पिछले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि में यह 3,41,568 करोड़ रुपये था, जो कि 11.18% की वृद्धि दर्शाता है।

3,79,760 करोड़ रुपये के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 1,56,949 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स (सीआईटी) (रिफंड के समायोजन के बाद) और प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) सहित 2,22,196 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) (रिफंड के समायोजन के बाद) शामिल है।

वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 17 जून, 2023 तक अग्रिम कर संग्रह 1,16,776 करोड़ रुपये का हुआ, जबकि इससे ठीक पहले वाले वित्त वर्ष यानी 2022-23 की इसी अवधि में अग्रिम कर संग्रह 1,02,707 करोड़ रुपये का हुआ था, जो कि 13.70% की वृद्धि दर्शाता है। 17 जून, 2023 तक हुए 1,16,776 करोड़ रुपये के अग्रिम कर संग्रह में 92,784 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स (सीआईटी) और 23,991 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में 17 जून, 2023 तक 39,578 करोड़ रुपये के रिफंड भी जारी किए गए, जो कि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए 30,414 करोड़ रुपये के रिफंड की तुलना में 30.13% अधिक है। ■

खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के दौरान की गई 830 एलएमटी धान की खरीद

गेहूं और धान की संयुक्त खरीद के लिए एमएसपी भुगतान पिछले साल के लिए कुल भुगतान 2,05,896 करोड़ रुपये के मुकाबले 2,26,829 करोड़ रुपये किया गया

खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2022-23 के दौरान भारत सरकार द्वारा धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन के तहत 19.06.2023 तक केंद्रीय पूल के लिए 830 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से अधिक धान की खरीद की गई। केएमएस 2022-23 के चल रहे धान खरीद कार्यों से अब तक 1.22 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और एमएसपी आउटफ्लो के साथ 1,71,000 करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में स्थानांतरित किए गए।

केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि परेशानी मुक्त खरीद संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं की जायें। खरीदे गए धान के बदले चावल की डिलीवरी भी प्रगति पर है और 830 एलएमटी धान (चावल के संदर्भ में 558 एलएमटी) की खरीद के बदले केंद्रीय पूल में लगभग 401 एलएमटी चावल 19.06.2023 तक प्राप्त किया गया है और 150 एलएमटी अभी तक प्राप्त होना बाकी है।

चालू रबी मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) 2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है। मौजूदा सीजन में 19.06.2023 तक गेहूं की प्रोग्रेसिव खरीद 262 एलएमटी है जो पिछले साल की कुल खरीद 188 एलएमटी से 74 एलएमटी अधिक है। पहले ही चल रहे गेहूं खरीद कार्यों से एमएसपी आउट फ्लो लगभग रु. 55,680 करोड़ रुपये के साथ लगभग 21.29 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। खरीद में प्रमुख योगदान तीन खरीददार राज्यों पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा से क्रमशः 121.27 एलएमटी, 70.98 एलएमटी और 63.17 एलएमटी की खरीद के साथ आया है।

गेहूं और धान की संयुक्त खरीद के लिए एमएसपी भुगतान पिछले साल के लिए कुल भुगतान 2,05,896 करोड़ रुपये के मुकाबले 2,26,829 करोड़ रुपये किया गया।

गेहूं और चावल की वर्तमान खरीद के साथ सरकारी अनाज में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार बनाए रखा गया है। गेहूं और चावल का संयुक्त स्टॉक 570 एलएमटी तक पहुंच गया है, जो देश को खाद्यान्न की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आरामदायक स्थिति में रखता है। ■

आधुनिक भारत के निर्माता

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी

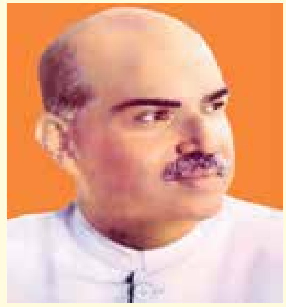

डॉ. मुकर्जी ने 'दो विधान, दो निशान और दो प्रधान' के खिलाफ प्रजा परिषद् के सत्याग्रह का समर्थन किया। उन्होंने इस मुद्दे को देश की जनता तक पहुंचाया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में प्रजा परिषद् के आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए देश भर में सार्वजनिक बैठकें आयोजित कीं

विकास आनंद

आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी का जन्म 6 जुलाई, 1901 को हुआ था। उनके पिता का नाम सर आशुतोष मुकर्जी था। डॉ. मुकर्जी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। डॉ. मुकर्जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वह एक शिक्षाविद्, बैरिस्टर, राजनीतिज्ञ और सर्वोत्कृष्ट मानवतावादी थे। अपनी कड़ी मेहनत और अकादमिक उत्कृष्टता के कारण वह 33 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने, यह शायद अकादमिक इतिहास में पहला उदाहरण था।

कॉलेज में एक छात्र के रूप में उनकी इच्छा एक पत्रकार बनने की थी, लेकिन जैसे–जैसे समय बीतता गया, उनकी रुचि राजनीति में बढ़ती गयी। उन्होंने जम्मू–कश्मीर का भारत में पूर्ण एकीकरण करने के उद्देश्य के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया।

अपने विचारों और गुणों के कारण डॉ. मुकर्जी ने महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किया। वह डॉ. मुकर्जी से इतने प्रभावित हुए कि जब 15 अगस्त, 1947 को भारत आजाद हुआ, तो महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आजादी के बाद गठित पहले मंत्रिमंडल में अन्य लोगों के अलावा दो लोगों को शामिल करने के लिए दबाव डाला। जिसमें एक डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी और दूसरे डॉ. बी.आर. अम्बेडकर थे। दिलचस्प बात यह है कि दोनों कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। पंडित नेहरू ने डॉ. मुकर्जी को वाणिज्य और उद्योग विभाग का दायित्व दिया। नेहरू के मंत्रिमंडल में एक मंत्री के रूप में उन्होंने एक ऐसे अमिट छाप छोड़ी, जिसने नए स्वतंत्र देश के औद्योगीकरण की मजबूत नींव रखी। उन्होंने देश को तेजी से औद्योगीकरण की ओर ले जाने का निर्णय लिया।

एक मंत्री के रूप में अपनी प्रभावशीलता के बावजूद डॉ. मुकर्जी ने शरणार्थी समस्याओं, कश्मीर मुद्दे से निपटने और पाकिस्तान के क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। जैसे–जैसे समय बीतता गया, उन्हें एहसास हुआ कि वह अब नेहरू की सरकार में काम करना संभव नहीं है और वह उन नीतियों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, जो उनके विचार, देश के सर्वोत्तम हित में नहीं थीं। अंततः 8 अप्रैल, 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।

नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने आरएसएस की मदद से 'जनसंघ' की स्थापना की। 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में जनसंघ की औपचारिक शुरुआत हुई और डॉ. मुकर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने।

डॉ. मुकर्जी ने 'दो विधान, दो निशान और दो प्रधान' के खिलाफ प्रजा परिषद् के सत्याग्रह का समर्थन किया। उन्होंने इस मुद्दे को देश की जनता तक पहुंचाया। उन्होंने जम्मू–कश्मीर में प्रजा परिषद् के आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए देश भर में सार्वजनिक बैठकें आयोजित कीं। डॉ. मुकर्जी आंदोलन को अहिंसक रखना चाहते थे। जम्मू–कश्मीर की स्थिति का आकलन करने के लिए डॉ. मुकर्जी ने श्री उमा शंकर त्रिवेदी और श्री जीवी देशपांडेय को जम्मू भेजने का निर्णय लिया, लेकिन दोनों को जम्मू–कश्मीर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने स्वयं बिना किसी मंजूरी या अनुमति के कश्मीर जाने का फैसला किया।

डॉ. मुकर्जी ने 8 मई, 1953 को नई दिल्ली से जम्मू–कश्मीर के लिए अपनी यात्रा आरंभ की। 11 मई को वे पठानकोट पहुंचे। पठानकोट में उनका भव्य स्वागत हुआ। डॉ. मुकर्जी शाम चार बजे माधोपुर चेक पोस्ट पहुंचे।

डॉ. मुकर्जी को ले जा रही जीप जैसे ही माधोपुर पुल के बीच पहुंची, उन्हें जम्मू–कश्मीर पुलिस ने रोक लिया। डॉ. मुकर्जी को उनके दो सहयोगियों गुरुदत्त वैद्य और टेकचंद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें जम्मू–कश्मीर के सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे, को डॉ. मुकर्जी ने वापस जाने और देश के लोगों को यह बताने के लिए कहा कि डॉ. मुकर्जी ने बिना परमिट के जम्मू–कश्मीर राज्य में प्रवेश कर लिया है। डॉ. मुकर्जी को श्रीनगर ले जाया गया। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें दो अन्य लोगों के साथ 23 जून,1953 को निशात गार्डन के पास एक झोपड़ी में उनकी रहस्यमय मृत्यु तक यानी 42 दिनों तक हिरासत में रखा गया। तब से उनकी पुण्य तिथि को 'बलिदान दिवस' के रूप में याद किया जाता है।

डॉ. मुकर्जी के अधूरे कार्य को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त करके पूरा किया।

सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण
साल
जनसभा
शिलान्यास
समारोह

सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण
साल
जनसभा

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91, शीर्षक कोडः UPHIN16701, डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2022-23
जुलाई प्रथम 2023 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 11–13 (प्रथम पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।